सांध्य दैनिक

श्रीकंचनपथ

RNI. Reg. No. CHHHIN/2009/30534
डाक पंजीयन क्रं.-छ.ग./दुर्ग/1000000029/2026-28

लीपा पोती नहीं सिर्फ सच

वर्ष- 17 अंक - 148 | www.shreekanchanpath.com | संस्थापक एवं प्रेरणास्रोत- स्व. श्रीमती रजनी अग्रवाल | भिलाई, शुक्रवार 13 मार्च 2026 | पृष्ठ 8- मूल्य 1/-

खास-खबर

छत्तीसगढ़ ओपन स्कूल बोर्ड का टाइम टेबल जारी, 16 मार्च से 12वीं और 17 मार्च से 10वीं की परीक्षा

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल ने कक्षा 10वीं (हाईस्कूल) और 12वीं (हायर सेकेंडरी) की बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इस वर्ष हिंदी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों की परीक्षाएं मार्च से अप्रैल 2026 के बीच आयोजित की जाएंगी। जारी कार्यक्रम के अनुसार हायर सेकेंडरी (12वीं) की सैद्धांतिक परीक्षा 16 मार्च 2026 से शुरू होगी, जबकि हाईस्कूल (10वीं) की परीक्षा 17 मार्च 2026 से प्रारंभ होगी। सभी परीक्षाएं एक ही पाली में सुबह 8:30 बजे से 11:45 बजे तक आयोजित की जाएंगी। बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार छात्रों को सुबह 8:30 बजे तक परीक्षा केंद्र में अपनी सीट पर बैठना होगा। इसके बाद 8:35 बजे उत्तरपुस्तिका वितरित की जाएगी, 8:40 बजे प्रश्नपत्र दिए जाएंगे और 8:45 बजे से उत्तर लेखन शुरू होगा। परीक्षा का समय 11:45 बजे तक निर्धारित किया गया है।

छत्तीसगढ़ का मौसम, बस्तर संभाग में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट

रायपुर। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही गर्मी के बीच मौसम विभाग ने दक्षिण छत्तीसगढ़ के लिए बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। विशेष रूप से बस्तर संभाग के कई जिलों में शुक्रवार से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 13 से 15 मार्च के बीच बस्तर क्षेत्र में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। यदि बारिश होती है तो तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक बिहार और झारखंड के बीच समुद्र तल से करीब 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक ट्रफ लाइन सक्रिय है। इसी सिस्टम के प्रभाव से छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बादल छाने और बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। जगदलपुर, बीजापुर समेत बस्तर संभाग के अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ गरज-चमक की स्थिति भी बन सकती है।

कोरबा में शरारती तत्वों ने गमले तोड़े, पाम ट्री को काटा

कोरबा। निगम के सौंदर्यीकरण पर शरारती तत्वों की नजर पड़ गई है। निगम ने सड़क के बीच डिवाइडर पर पौधे-फूल लगाए हैं, जिन्हें शरारती तत्वों ने नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। सियान सदन से घंटाघर के बीच लगे फास्टर पाम ट्री के ऊपरी हिस्से को काट दिया है। सड़क के बीच में इमोजी गमले लगाए गए हैं, जिसे नीचे गिराया गया है। निगम प्रशासन ने शरारती तत्वों पर कार्रवाई के लिए सिविल लाइन थाने में सूचना दर्ज कराई है।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिली 15.70 करोड़ की अतिरिक्त सहायता

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति ने वर्ष 2025 के दौरान आई बाढ़, फ्लैश फ्लड, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवाती तूफान 'मोन्था' जैसी आपदाओं से प्रभावित राज्यों के लिए 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में केंद्र के इस अतिरिक्त सहयोग के लिए केंद्रीय गृह मंत्री का आभार माना है।

केंद्र सरकार द्वारा यह सहायता राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) से जारी की जाएगी, ताकि प्रभावित राज्यों में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। समिति के निर्णय के अनुसार छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता स्वीकृत की गई है।

केंद्र सरकार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। आपदा की स्थिति में प्रभावित राज्यों को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है।

अतिरिक्त सहायता राज्यों को पहले से उपलब्ध कराए गए संसाधनों के अतिरिक्त है। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार ने राज्यों को आपदा प्रबंधन के लिए बड़ी राशि पहले ही जारी कर दी है। State Disaster Response Fund (SDRF) के तहत 28 राज्यों को 20,735.20 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जबकि National Disaster Response Fund (NDRF) के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है।

घरेलू एलपीजी की कालाबाजारी : रायपुर में खाद्य विभाग ने जब्त किए 350 से ज्यादा सिलेंडर

राजधानी रायपुर में खाद्य विभाग की टीम ने होटल में मारी रेड, सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। रायपुर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग और कालाबाजारी के खिलाफजिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए बड़ा अभियान चलाया है। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग की संयुक्त जांच टीम ने जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में छापेमारी की। इस दौरान कई स्थानों पर कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में गैस सिलेंडर जब्त किए गए।

जांच के दौरान धरसींवा विकासखंड के सेजबहार स्थित कमल होटल में घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग करते पाए जाने पर 14.2 किलोग्राम क्षमता के 8 सिलेंडर जब्त किए गए। वहीं, बाबूलाल चिकन सेंटर से भी घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग पाए जाने पर 3 घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। इसी तरह अभनपुर-नवापारा क्षेत्र में रवि ग्लास एंड प्लाइवुड में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आया। यहां से 14.2 किलोग्राम क्षमता के 26 घरेलू सिलेंडर, 19 किलोग्राम क्षमता के 2 व्यावसायिक सिलेंडर और 5 किलोग्राम क्षमता के 4 सिलेंडर जब्त किए गए।

गरियाबंद में 19 सिलेंडर जब्त

गरियाबंद जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग के विरुद्ध खाद्य विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम ने जिले के विभिन्न होटल एवं रेस्टोरेंट में छापामार कार्रवाई करते हुए 19 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। इनमें 11 भरे हुए तथा 8 खाली सिलेंडर शामिल हैं। जिला खाद्य अधिकारी अरविंद दुबे ने बताया कि कलेक्टर द्वारा जिले के सभी गैस वितरकों को तेल कंपनियों के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार के मामलों में आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं संबंधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

गैस एजेंसी की जांच में स्टॉक में बड़ा अंतर

इसके अलावा खाद्य विभाग की टीम ने कोरासी इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेंसी की भी जांच की, जहां रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर पाया गया। जांच में 14.2 किलोग्राम क्षमता के 101 भरे और 64 खाली घरेलू सिलेंडर और 19 किलोग्राम क्षमता के 23 खाली व्यावसायिक सिलेंडर कम पाए गए। इस अनियमितता के चलते एजेंसी के गोदाम में उपलब्ध कुल 355 घरेलू और व्यावसायिक सिलेंडरों को जब्त कर एजेंसी की सुपुर्दगी में दिया गया है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

अफीम की खेती पर सीएम सख्त सभी कलेक्टरों को सर्वे का निर्देश

15 दिन में प्रमाण पत्र सहित रिपोर्ट देने के निर्देश

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। दुर्ग और बलरामपुर जिलों में अफीम की अवैध खेती के मामले सामने आने के बाद कांग्रेस नेता प्रदेश सरकार को घेर रहे हैं। इस मामले में पुलिस व प्रशासन द्वारा आरोपियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इस बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को अपने-अपने जिलों में संभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वे कराने का निर्देश दिया हैं।

सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि राज्य के किसी भी क्षेत्र में अवैध रूप से अफीम की खेती न हो रही हो। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 15 दिवस के भीतर प्रमाण पत्र सहित विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री साय ने कहा है कि राज्य में अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन और कारोबार के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है और ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के पालन में आयुक्त भू-अभिलेख द्वारा राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को सर्वे कर जांच रिपोर्ट और उनके जिले में अफीम की खेती नहीं किए जाने संबंधी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में पत्र जारी किया गया है।

ई-चालान निपटाने का अंतिम मौका, लोक अदालत कल

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। यदि आपके वाहन का ई-चालान लंबे समय से लंबित है, तो 14 मार्च की तारीख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। राजधानी समेत पूरे प्रदेश में इस दिन लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बकाया जुर्माना भरने का यह अंतिम अवसर होगा, जिसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय और पुलिस विभाग के समन्वय से आयोजित यह लोक अदालत भौतिक उपस्थिति और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोनों माध्यमों से संचालित होगी।

रायपुर में अब तक छह हजार से अधिक ई-चालानों का पंजीयन किया जा चुका है। जो लोग अदालत में उपस्थित नहीं हो सकते, वे ऑनलाइन माध्यम से भी अपने मामलों का निपटारा करा सकेंगे। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, वाहन चालकों को चालान जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। नियमानुसार पहले 90 दिनों तक पोर्टल पर भुगतान का अवसर मिलता है। इसके बाद अगले 45 दिनों के भीतर मामला कोर्ट में ट्रांसफर होने पर भी भुगतान की मोहलत रहती है। इस प्रकार कुल 135 दिनों की अवधि के बाद भी यदि जुर्माना जमा नहीं किया जाता, तो संबंधित वाहन को जब्त किया जा सकता है। इस लोक अदालत में केवल वही ई-चालान शामिल किए गए हैं, जो 15 अक्टूबर 2025 से पहले जारी हुए हैं और वर्तमान में न्यायालय में लंबित हैं। वाहन मालिकों को मोबाइल कॉल और व्हाट्सएप के माध्यम से लगातार सूचनाएं भी भेजी जा रही हैं, ताकि वे इस अवसर का लाभ उठा सकें।

ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई कोमा में! ट्रंप ने कहा- जिंदा हैं लेकिन गंभीर रूप से घायल

तेहरान। ईरान के नए नियुक्त सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई के बारे में खबर है कि वह कथित तौर पर कोमा में हैं। सूत्रों के अनुसार एक हवाई हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनका एक पैर काटना पड़ा है। यह दावा ब्रिटेन के टैबलॉयड अखबार द सन की एक रिपोर्ट में किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार 56 वर्षीय मोजतबा खामेनेई उस एयर स्ट्राइक में बुरी तरह घायल हो गए थे, जिसमें उनके पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। बताया गया है कि हमले के बाद उन्हें गंभीर हालत में तेहरान में इलाज के लिए ले जाया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें 28 फरवरी को हुए उसी एयर स्ट्राइक में चोटें आईं, जिसमें 86 वर्षीय अली खामेनेई की हत्या हुई थी या किसी अन्य हमले में। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर की स्थिति को लेकर बड़ा बयान दिया है। फॉक्स न्यूज रेडियो से बातचीत के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि मोजतबा खामेनेई जीवित हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वह शायद जिंदा हैं, लेकिन संभव है कि उन्हें गंभीर चोटें आई हों।

क्रिकेटर हार्दिक के खिलाफ यूपी में शिकायत

हाथरस । भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। टी20 विश्व कप 2026 की जीत के जश्न के दौरान राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे के कथित अपमान के आरोप में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। इस मामले ने करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत करने का दावा किया जा रहा है।

हाथरस गेट थाना क्षेत्र के गांव नगला नंदू निवासी अधिवक्ता विश्वप्रताप सिंह राणा ने पुलिस अधीक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री को एक प्रार्थना पत्र भेजकर हार्दिक पांड्या के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल मैच में भारत की जीत के बाद हार्दिक पांड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पांड्या को एक महिला के साथ कथित तौर पर राष्ट्रध्वज ओढ़कर आपत्तिजनक स्थिति में दिखाया गया है। अधिवक्ता का आरोप है कि यह कृत्य राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा के खिलाफहै और इसने देश के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है।

युवती और गर्भस्थ शिशु की मौतः मकान मालिक गिरफ्तार

घर से निकालने की धमकी देकर युवती से बनाता था संबंध, प्रेग्नेंट हुई तो दवा खिलाकर मारा

बालोद । डौंडीलोहारा थाना क्षेत्र में एक अविवाहित युवती और उसके गर्भस्थ शिशु की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी मकान मालिक को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी लंबे समय से युवती को धमकाकर उससे अवैध संबंध बना रहा था और गर्भवती होने के बाद उसे दवाई खिलाकर मामले को छिपाने की कोशिश की गई।

पुलिस के अनुसार पीड़िता अपनी मां, दो बहनों और एक भाई के साथ पिछले लगभग तीन वर्षों से डौंडीलोहारा के रामनगर निवासी सुनील कुमार घरडे के मकान में किराए पर रह रही थी। 10 मार्च को डौंडीलोहारा थाना में युवती की मौत की सूचना मर्ग दर्ज की गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच और पूछताछ में कई संदिग्ध तथ्य सामने आए। पुलिस को जानकारी मिली कि आरोपी सुनील कुमार घरडे युवती को लगातार धमकाकर उसके साथ संबंध बना रहा था। युवती के गर्भवती होने के बाद आरोपी ने उसे दवाई खिलाकर घटना को दबाने का प्रयास किया, जिससे उसकी और गर्भस्थ शिशु की मौत हो गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच कर रही है।

रायपुर के होटल में मिली दो विदेशी युवतियों पर एफआईआर, पुलिस करेगी उजबेकिस्तान डिपोर्ट

होटल एरिना बुटिक से पुलिस ने पकड़ा था, दो माह में नहीं दे सकी कोई जानकारी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा इलाके के होटल एरिना बुटिक में मिली दो उजबेकिस्तानी महिलाओं के खिलाफपुलिस ने दो माह की जांच के बाद एफआईआर दर्ज की है। युवतियों पर संदिग्ध गतिविधियों पर शामिल होने का आरोप लगा था। पुलिस की जांच के दौरान युवतियां पासपोर्ट, वीजा संबंधित दस्तावेज नहीं दे पाई, तो उन्हें हिरासत में लेकर रायपुर सेंट्रल जेल परिसर में बने डिटेंसन सेंटर में रखा गया था।

बता दें 9 जनवरी 2026 को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 'होटल एरिना बुटिक' में दो विदेशी युवतिां ठहरी हुई हैं, जिनकी गतिविधियां संदिग्ध हैं। सूचना पर तेलीबांधा पुलिस की टीम ने दबिश दी और दोनो को हिरासत में लिया था। 10 मार्च 2026 तक बार-बार मौका देने के बावजूद दोनों महिलाएं भारत में रहने या यात्रा करने का कोई भी वैध प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाईं।

इसके बाद पुलिस ने उनके खिलाफआव्रजन और विदेशी विषयक अधिनियम 2025 की धारा 3, 21 और 23 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस अब दूतावास के जरिए इन्हें वापस इनके देश भेजने की तैयारी कर रही है।

पुलिस अधिकारी ने कहा- दूतावास से संपर्क किया गया

तेलीबांधा निरीक्षक अविनाश सिंह के अनुसार विदेशी युवतियों को जनवरी माह में हिरासत में लेकर डिटेंसन सेंटर भेजा था। दो महीने तक युवतियों ने अपने से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी है। युवतियों पर एफआईआर दर्ज करके दूतावास से संपर्क किया गया है। दूतावास की मदद से युवतियों को डिपोर्ट किया जाएगा।

संपादकीय

मृत्यु में गरिमा

इच्छामृत्यु के बाबत स्पष्ट कानून जरूरी

किसी भी समाज में यह प्रबल धारणा रही है कि परिवार के किसी सदस्य की तब तक सेवा की जाए, जब तक उसके प्राण कुदरती तौर पर न निकल जाएं। खासकर भारतीय समाज में इस मुद्दे को लेकर गहरी संवेदनशीलता रही है। कई स्थानों पर तो अपने आत्मीय की मृत्यु के बाद भी उसे वर्षों तक जीवन लौटने की आस में घर पर रखा गया। लेकिन जब कोई अपना प्रिय उस स्थिति में पहुंच जाए, जहां से सामान्य जीवन में लौट पाना संभव ही न हो, तो बदलते वक्त के साथ कानून के दायरे में उसकी मुक्ति की भी बात होने लगी है। हाल ही में देश के सुप्रीम कोर्ट का 13 वर्ष से कोमा में रहने वाले एक युवा के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने का निर्णय, जीवन के अंतिम चरण की देखभाल पर भारत में विकसित होते न्यायशास्त्र में नया मोड़ है। किसी असाध्य स्थिति में कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने वाला यह फैसला, अदालत द्वारा पहले से निर्धारित प्रक्रिया का पहला व्यावहारिक प्रयोग है। निस्संदेह, यह मामला उन रोगियों के परिवारों के सामने उपस्थित पीड़ादायक दुविधा को ही उजागर करता है, जिनके ठीक होने की कोई वास्तविक संभावना नहीं होती। जो महज चिकित्सकीय मदद से ही जीवित रहते हैं। इस मामले में चिकित्सा बोर्डों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि निरंतर उपचार का कोई चिकित्सीय उद्देश्य नहीं था। इससे केवल जैविक अस्तित्व को ही लंबा खींच दिया गया। बहरहाल, इस बाबत अदालत की स्वीकृति एक कठिन सत्य को स्वीकार करती है कि जीवन की गरिमा, मृत्यु में भी गरिमा तक विस्तारित होनी चाहिए। निस्संदेह, भारत में इच्छामृत्यु पर कानूनी प्रगति धीमी रही है। इस मामले में पहली बार अरुणा शानबाग मामले में ध्यान दिया गया था। वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के अंतर्गत गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार देने के साथ यह मुद्दा अपने चरम पर पहुंचा।

> “ देश के सुप्रीम कोर्ट का 13 वर्ष से कोमा में रहने वाले एक युवा के लिये निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति देने का निर्णय, जीवन के अंतिम चरण की देखभाल पर भारत में विकसित होते न्यायशास्त्र में नया मोड़ है। किसी असाध्य स्थिति में कृत्रिम जीवन रक्षक प्रणाली हटाने की अनुमति देने वाला यह फैसला, अदालत द्वारा पहले से निर्धारित प्रक्रिया का पहला व्यावहारिक प्रयोग है।

दरअसल, इच्छामृत्यु से जुड़ी दुविधा, इससे जुड़े सिद्धांतों के क्रियान्वयन की अनिश्चितता को लेकर बनी रही है। जिसके चलते परिवारों व डॉक्टरों को जटिल प्रकिया व कानूनी चिंताओं का सामना करना पड़ रहा है। निस्संदेह, हालिया फैसले से भी न्यायिक दिशा-निर्देशों मात्र पर निर्भर रहने की सीमाएं उजागर हुई हैं। बल्कि यहां तक कि देश की शीर्ष अदालत ने भी निष्क्रिय इच्छामृत्यु, लिविंग विल और जीवन को लेकर अंतिम निर्णय को नियंत्रित करने वाले व्यापक कानून की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। निस्संदेह, ऐसे कानून में नैतिक संवेदनशीलता और प्रक्रियात्मक स्पष्टता के बीच बेहद संतुलन होना चाहिए। यह प्रक्रिया कमजोर रोगियों को दुर्व्यवहार से बचाते हुए, यह भी सुनिश्चित करे कि परिवार और चिकित्सा पेशेवर कानूनी परिणामों के भय के बिना कार्य कर सकें। इस मामले में स्पष्ट प्रोटोकॉल, पारदर्शी चिकित्सा मूल्यांकन और रोगी की स्वायत्तता का सम्मान आवश्यक है। अंतत, निष्कर्ष यह भी है कि जब उपचार असंभव हो तो चिकित्सा उपायों से रोगी की पीड़ा को लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए। निस्संदेह, शीर्ष अदालत की कारगर सलाह के मद्देनजर देश के नीति-नियंताओं को एक मानवीय कानूनी ढांचा तैयार करने के बारे में गंभीरता से सोचना चहिए। जो टाली न जा सकने वाली विषम स्थिति में व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने व मरने की अनुमति दे सके। निस्संदेह, देश में इस बाबत एक संवेदनशील कानून बनाने की सख्त जरूरत महसूस की जा रही है। साथ ही ऐसा कानून बनाते वक्त मानवीय संवेदनशीलता तथा कानूनी सुरक्षा कवच के बीच संतुलन बनाना भी उतना ही जरूरी होगा। वहीं हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि निहित स्वार्थी तत्वों द्वारा संकीर्ण लक्ष्यों को पूरा करने के लिये किसी व्यक्ति की दबाव में इच्छामृत्यु के लिये परिस्थितियां पैदा न की जा सकें। दुनिया के तमाम विकसित देशों में इस आशंका के चलते ही इच्छामुत्यु को कानूनी रूप देने से परहेज किया गया है। यह जटिल मामला भी है, जिसके निर्धारण के लिये कानूनी स्पष्टता और मामले की गहन निगरानी भी उतनी ही जरूरी है।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल में अग्रणी भूमिका निभा रहा है योग

प्रतापराव जाधव

बीते दशक में योग को केवल पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति के रूप में ही नहीं सराहा गया, बल्कि उसे उत्त रोत्तवर रूप से स्वास्थ्य और कल्याण के लिए साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोण के रूप में भी पहचाना जाने लगा है। वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और वैश्विक सहयोग अब हमें योग को केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, बल्कि एक सशक्त जन-स्वास्थ्य हस्तक्षेप समझने में भी मदद कर रहे हैं।

मोरारजी देसाई राष्ट्री य योग संस्था न (एमडीएनआईवाई) को पारंपरिक चिकित्सा (योग) के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया है और योग अनुसंधान में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका और भी मज़बूती प्रदान करते हुए वर्ष 2025-2029 के लिए इसे फिर से निमित किया गया है। यह पहचान गैर-संचारी रोग (एनसीडी) के लिए साक्ष्य-आधारित योग हस्तिक्षेपों को बढ़ावा देने में संस्था न की बढ़ती भूमिका को दिखाती है। इस पहल के प्रमुख साझेदारों में आयुष मंत्रालय, एम्सा दिल्ली, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद, और इंस्टीट्यूट ऑफ़ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, दिल्ली शामिल हैं।

इन सहयोगों के माध्यम से केंद्र मधुमेह, मोटापा और तनाव से संबंधित विकारों जैसे गैर-संचारी रोगों के लिए योग-आधारित हस्तक्षेपों पर तकनीकी दिशानिर्देश विकसित कर रहा है और अनुसंधान को आगे बढ़ा रहा है। इन प्रयासों में अंतरराष्ट्रीय संगठन भी साझेदारी कर रहे हैं, जिससे योग की वैज्ञानिक आधारशिला और मजबूत हो रही है तथा निवारक स्वास्थ्य देखभाल के लिए व्यापक रूप से लागू किए जा सकने वाले, किफायती और साक्ष्य-समर्थित प्रभावी साधन के तौर पर योग की क्षमता प्रदर्शित हो रही है।

संस्थागत स्तर पर एमडीएनआईवाई योग की वैज्ञानिक आधारशिला को मजबूती प्रदान करना जारी रखे हुए है। शरीर क्रिया विज्ञान, जैव रसायन, बायोमैकेनिक्स और मनोविज्ञान की अनुसंधान प्रयोगशालाओं के माध्यम से यह संस्थान योग के मनो-शारीरिक और जैव-रासायनिक प्रभावों, उम्र बढ़ने में इसकी भूमिका तथा जीवनशैली से जुड़े विकारों पर इसके प्रभाव का अध्ययन करता है। यह कार्य पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ जोड़ने की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

डिजिटल प्लेटफॉर्मों ने योग की पहुँच को और अधिक बढ़ाया है, जिससे साक्ष्य-आधारित पद्धतियाँ सीधे लोगों के दैनिक जीवन का हिस्सा बन रही हैं। m-Yoga मोबाइल एप्लिकेशन और Y-Break प्रोटोकॉल जैसे प्रयास यह दिखाते हैं कि योग की प्रामाणिकता और चिकित्सकीय महत्वि बनाए रखते हुए उसे बड़े स्तर पर पहुँचाया जा सकता है। विश्वै स्वारस्य् च संगठन के सहयोग से विकसित किए गए m-Yoga प्लेटफॉर्म पर 1.1 लाख से अधिक डाउनलोड दर्ज किए जा चुके हैं, जो सुलभ डिजिटल वेलनेस टूल्स में बढ़ती रुचि को दर्शाता है। वहीं कार्यस्थल योग कार्यक्रम Y-Break — जो काम के दौरान 5-10 मिनट का सरल योग ब्रेक है — से अब तक 33 लाख से अधिक सरकारी अधिकारियों को लाभ मिल चुका है।

इन पहलों से प्राप्त अनुसंधान निष्कर्ष और सहभागिता विश्लेषण अत्यंत उत्साहजनक हैं। Y Break अभ्यास से कुछ ही सप्ताहों में अनुभूत तनाव में लगभग 40 प्रतिशत तक कमी देखी गई है। अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि इससे मानसिक सतर्कता, भावनात्मक दृढ़ता और निर्णय-क्षमता में सुधार होता है। इसके साथ-साथ कॉर्टिसोल स्तर जैसे शारीरिक संकेतकों में भी सकारात्मक परिवर्तन पाए गए हैं।

शारीरिक लाभों में गर्दन, कंधे और कमर के दर्द में कमी, श्वास अभ्यास से सांस लेने की क्षमता में सुधार और संपूर्ण जीवन शक्ति में वृद्धि शामिल हैं— ये परिणाम विशेषकर आज के निष्क्रिय, स्क्रीन-आधारित कार्यस्थलों में प्रासंगिक हैं। Y-Break अभ्यास ने अनुपस्थिति में कमी लाने , कर्मचारियों के मनोबल में सुधार लाने, और कार्य-जीवन में स्वस्थ संतुलन कायम करने में भी योगदान दिया है, जो व्यक्तिगत और संगठनात्मक कल्याण दोनों को मजबूत बनाने की योग की क्षमता को दर्शाता है।

एमडीएनआईवाई और केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा सम्मेलन-2026 के दौरान भी वैज्ञानिक प्रमाण के महत्वो पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने यह रेखांकित किया कि सुदृढ़ अनुसंधान, अंतरविषयक सहयोग, और प्रभावी डिजिटल सहभागिता आधुनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों में योग को एकीकृत करने और स्पष्टि स्वास्थ्य परिणाम सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य हैं।

ये घटनाक्रम योग के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं। अब इसे केवल व्यक्तिगत कल्याण के अभ्यास के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह उत्ततरोत्तेर रूप से जन-स्वास्थ्य, कौशल विकास और वेलनेस आधारित रोजगार के अवसरों के एक मार्ग के रूप में उभर रहा है। योग परंपरा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के साथ जोड़ते हुए ग्लोबल योग क्रांति की प्रेरक शक्ति के रूप में उभर रहा है तथा अंतरराष्ट्रीय वेलनेस क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को और मजबूत कर रहा है।

जैसे-जैसे हम 13 मार्च के करीब पहुँच रहे हैं, जो 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 100-दिन के काउंटडाउन का संकेत है, यह हमें इस बारे में सोचने का अवसर देता है कि किस प्रकार योग एक प्राचीन पद्धति से लेकर वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त, साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य और कल्याण मार्ग के रूप में विकसित हो गया है। ये सौ दिन हमें याद दिलाएं कि हम दैनिक योग अभ्यास शुरू करें या उसे नवीनीकृत करें, और अपने परिवार, मित्रों और समुदायों को योग को जीवन जीने का तरीका बनाने के लिए प्रेरित करें।

योग को दैनिक जीवन में शामिल करके, हम केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को ही मजबूत नहीं करते, बल्कि सामूहिक कल्याण, संगठनात्मक दक्षता और सामाजिक समरसता को भी बढ़ावा देते हैं। आज, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से, भारत योग की अनंत ज्ञान परंपरा को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और सार्वभौमिक रूप से सुलभ मार्ग में बदलने का अगला निर्णायक कदम उठा रहा है, जो वैश्विक स्वास्थ्य, संतुलन और कल्याण के लिए मार्गदर्शक बन सकेगा।

करिअर का चुनाव किसी भी बेमकसद युद्ध की तरह न हो

एन. रघुरामन

वह हॉलीवुड में कोई बॉक्स ऑफिस एनालिस्ट नहीं, बस हाई स्कूल का एक सीनियर छात्र है। लेकिन उसे अच्छे से पता है कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। वह फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहता है। अभिनय, निर्देशन या संगीत नहीं, उसकी रुचि फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन में है। अबदी बूटान को लगता है कि इस क्षेत्र में पैसा जल्दी कमाया जा सकता है। तो अभी अबदी क्या कर रहा है?

खाली समय में अबदी अपने बॉक्स ऑफिस अनुमानों की स्प्रेडशीट बनाता है। उसके अनुमान एडवांस टिकट बिक्री और ऐसे कई फैक्टर्स पर आधारित होते हैं, जिनके बारे में जेन-जी के तौर पर वह सोचता है कि उसकी उम्र के लोगों को कोई फिल्म कितनी आकर्षक लगेगी। बॉक्स ऑफिस को लेकर यह चार्टिंग उसे इंडस्ट्री, आबादी के फैलाव, जियोग्राफी, दुनिया की पसंद, तकनीकी विशेषज्ञता, स्टोरी लिखने के विचार और फिल्म के संगीत की समझ देती है।

ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही उसके अनुमान सही रहे। उसने भी गलतियां की, लेकिन स्प्रेडशीट पर काम जारी रखा। नवंबर, 2025 में हॉलीवुड में दो फिल्में रिलीज हुईं- 'विकेड : फॉर गुड' और 'जूटोपिया 2'। पहली फिल्म के लिए उसने टिकट बिक्री के जरूरत से अधिक अनुमान लगाने की गलती की। लेकिन दूसरी के बारे में उसने कहा कि यह दुनिया भर में 1.8 बिलियन डॉलर कमाएगी और फिल्म ने 1.9 बिलियन डॉलर कमाए।

फिल्म प्रेमी जेन-जी युवा अब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं और यह जानना चाहते हैं कि उनकी पसंदीदा फिल्में पैसे कमाने में सफल होंगी या नहीं। जब उन्हें पता चलता है कि फिल्म बढ़िया कमाई कर रही है तो कहीं न कहीं उनके मन में यह भी आता है कि उस पर किया खर्च सफल रहा।

हैरत नहीं कि इस बिजनेस में आंकड़ों की पड़ताल करने वाले अनुभवी लोगों के साथ आज के युवा भी अबदी के कैलकुलेशन पर नजर रखते हैं। मुझे अबदी के बारे में पढ़ी हुई ये बातें तब याद आईं, जब मैं एक युवा पोस्ट ग्रेजुएट का रेज्यूमे देख रहा था। उसने पांच साल में तीन अलग-अलग क्षेत्रों में काम किया और अब चौथे ऐसे क्षेत्र में करियर तलाश रहा था, जिसका उसकी पढ़ाई से कोई नाता नहीं था। जब उससे पूछा गया कि इन तीन क्षेत्रों से उसने क्या सीखा, तो उसके पास कोई ठोस जवाब नहीं था।

अपने कामों को लेकर वह एक भी साझा कड़ी नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। वह करियर नहीं बना रहा था, बल्कि संयोगवश हो रही घटनाओं में बस गुजारा कर रहा था। किसी दीर्घकालीन लक्ष्य के बिना करियर चुनना ऐसा ही है, जैसे बिना मकसद युद्ध छेड़ देना। जैसे कोई आक्रमणकारी देश किसी भी वक्त खुद को विजेता घोषित कर सकता है, वैसे ही कोई युवा भी अपने रेज्यूमे में लिख सकता है कि उसे 'ए, बी, सी जैसी कई जगहों का अनुभव है।'

लेकिन यह नहीं समझा पाता कि इतने वर्ष उसने इन क्षेत्रों में क्यों बिताए? स्कूली दिनों में ही 'स्प्रेडशीट्स' पर काम करना बताता है कि इसे आप हॉबी के तौर पर नहीं, बल्कि भविष्य की सफलता के डेटा प्वाइंट्स के तौर पर मान रहे हैं। आपका पहले दिन से सही होना जरूरी नहीं। आप गलतियां कर सकते हैं, जो आपके लिए सीख बन सकती है। सफलता में समय लग सकता है।

आपके जीवन का 'बॉक्स ऑफिस' पहले ही साल में बिलियन डॉलर तक भले ना पहुंचे, लेकिन अगर आप जल्दी शुरुआत करते हैं और उसे बनाए रखते हैं तो खुद को हायरिंग मैनेजर के सामने कभी ऐसे खड़ा नहीं पाएंगे, जहां यह न समझा पाओ कि यहां तक कैसे पहुंचे। आपको कभी कामचलाऊ नौकरी से समझौता नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद इंडस्ट्री चलाने में व्यस्त होंगे।

फंडा यह है कि अबदी की तरह जल्दी करियर चुनिए और स्कूली दिनों से ही उस पर काम शुरू कीजिए। बिना साफउद्देश्य के रास्ते में आए हर करियर में भटकते रहना आपको अनुभवी नहीं, बल्कि हालात का मारा बना देता है।

युद्ध में सच्चाई और नैरेटिव के बीच की धुंधली रेखा

श्याम भटिया

सदा से युद्धों के दौरान सरकारें नैरेटिव गढ़ती रही हैं। लेकिन जब आधिकारिक संदेश व डिजिटली गढ़ी खबरें एक साथ हों, तो सच और नैरेटिव के बीच रेखा खतरनाक रूप से धुंधली हो जाती है। सोशल मीडिया के दौर में युद्धक्षेत्र के दावे सत्यापन से पूर्व ही दुनिया में फैल जाते हैं। ईरान और इस्राइल के बीच आरंभिक झड़पों के कुछ ही घंटों में, नाटकीय वीडियो ऑनलाइन चलने लगीं, जिनमें दावा किया गया कि लड़ाकू जहाज मार गिराए और शहर मलबे में तब्दील हो गए। जल्द ही कई वीडियो मनगढ़ंत निकले। कुछ क्लिप तो वीडियो गेम्स फुटेज निकलीं। कुछ शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनायी लगती हैं- ऐसी सामग्री जिसके पत्रकारों द्वारा सत्यापन से पूर्व ही दुनिया यकीन कर ले।

ऐसे ही एक उदाहरण में, बहुत ज़्यादा शेयर किए क्लिप में दावा किया गया कि एक अमेरिकी युद्धपोत ने ईरानी लड़ाकू जहाज़ मार गिराया है, बाद में शिनाख्त हुई कि यह तो वीडियो गेम 'वॉर थंडर' का फुटेज है। इस वीडियो को ऑनलाइन लाखों व्यूज़ मिले व 'फैक्ट-चेकर्स द्वारा गेम फुटेज साबित करने के बाद और इसे डिलीट करने से पूर्व ग्रेग एबॉट तक ने शेयर किया। समीक्षकों ने पाया कि फुटेज में दिखे हथियार दूसरे विश्वयुद्ध के वक्त के थे, जिससे यह क्लिप मनगढ़ंत निकली।

एक और मामले में, एक वायरल वीडियो में ईरानी मिसाइल हमलों से तेल अवीव तबाह होता दिखा, बाद में विश्लेषकों ने इसकी शिनाख्त बतौर एआई निर्मित रील की। जब तक इस हेरफेर का खुलासा हुआ, तब तक क्लिप को लाखों लोग देख चुके थे। ऐसी सामग्री सोशल मीडिया पर तेज़ी से फैलती है। अक्सर असलियत सामने आने से पूर्व ही बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच जाती है।

यह घटनाक्रम वर्तमान दौर की युद्ध कवरेज में एक बड़ी समस्या पेश करता है। युद्ध के मैदान के शुरुआती दावे अक्सर सबसे कम भरोसेमंद होते हैं, तथापि डिजिटल युग में पत्रकारों द्वारा सत्यापित करने से पूर्व ही दुनिया में फैल जाते हैं। लंदन के टॉक रेडियो स्टेशन एलबीसी पर ईरान युद्ध पर चर्चा सुनते हुए, मैंने हाल ही में एक प्रस्तोता को यह अनुमान लगाते सुना कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स किसी प्रदर्शनकारी को मारने वाले को पुरस्कृत कर रहे हैं। कोई सबूत नहीं दिया गया, फिर भी यह बात खबर देने के अंदाज़ में कही गई। एक सदी से भी पूर्व, अमेरिकी सीनेटर हाइरम जॉनसन ने कहा था 'जब युद्ध होता है, तो सबसे पहली मौत सच की होती है'। वैसे ये कहावत पुरानी है, फिर भी मौजूदा संघर्ष संबंधी दावों की बाढ़ बताती है कि यह पूर्ववत् प्रासंगिक है। हालांकि, सवाल है कि आज के दौर में अन्य युद्धों की तुलना में ईरान-इस्राइल संघर्ष की खबरें इतनी अलग-अलग सी क्यों हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले के दौरान, पश्चिमी टीवी नेटवर्क और अखबारों ने अग्रिम मोर्चे पर पत्रकारों की टीमें तैनात की थीं। कीव, खार्किव और यहां तक युद्ध के मैदान से निरंतर रिपोर्टिंग ने पत्रकारों को सरकार द्वारा किए जा रहे दावों की असलियत परखने का मौका दिया। लेकिन, ईरान से जुड़ा संघर्ष बहुत अलग दिखता है। जहां ईरान में चंद पश्चिमी रिपोर्टर काम कर रहे हैं वहीं इस्राइली सैन्य सेंसरशिप युद्ध-विवरण की रिपोर्टिंग पर अंकुश लगा रही है। नतीजन, मिसाइल हमलों, हताहतों और सैन्य हानि बारे जो जानकारी ज्यादातर फैल रही है, वह रिपोर्टरों से नहीं, बल्कि सरकारों, सेना प्रवक्ताओं और सोशल-मीडिया पोस्टों के जरिए आती है।

मध्य-पूर्व में भी, अल जज़ीरा जैसे क्षेत्रीय चैनल कई पश्चिमी समकक्षों के मुकाबले अब ज़्यादा टिकाऊ कवरेज कर रहे हैं, विदेशी मीडिया के लोकल ब्यूरो पिछले दो दशकों में इस पूरे इलाके में लगातार सिकुड़े। नतीजन, यह ऐसा युद्ध है जिस पर चर्चा तो खूब हो रही, लेकिन हैरानी है कि खबरें देने वाली स्वतंत्र पत्रकारिता बहुत कम है। मिसाइल हमलों और हवाई हमले की चेतावनियों की रिपोर्टिंग पर गौर करें। ईरान-इस्राइल के बीच हालिया हमलों के दौरान, ऐसी खबरें चलीं जिनमें बताया गया कि यरुशलम में हवाई हमला चेतावनी सायरन बार-बार बज रहे हैं। अगर यह सच है, तो यह इस्राइल की हवाई-रक्षा प्रणाली में मिसाइलों की होती निरंतर घुसपैठ और शहर में बमबारी का स्तर दिखाता है, जो पहले शायद ही कभी देखा गया। फिर भी, वहां मौजूद रिपोर्टरों से लगातार सत्यापन मुश्किल बन गया है। मध्य इस्राइल में कुछ मिसाइल चेतावनियों की खबरें हैं। लेकिन यरुशलम में बार-बार अलर्ट सायरन बजने की खबर इलाके में मौजूद रिपोर्टरों से बहुत कम आई। हताहतों के आंकड़े भी ऐसी ही समस्या दिखाते हैं। ईरानी अधिकारियों ने बताया कि इस्राइली हमलों में आम लोगों को भारी नुकसान हुआ। वहीं इस्राइली अधिकारी वरिष्ठ ईरानी कमांडरों के मारे जाने और मिलिट्री ठिकानों को नुकसान पर ज़ोर देते हैं। हालांकि, स्वतंत्र सत्यापन बहुत कम है। ईरान ने युद्ध दौरान समय-समय पर इंटरनेट पर रोक लगाई, जबकि इस्राइली सरकार ने कुछ ऑपरेशंस के ब्यौरे पर सैन्य सेंसरशिप रखी। नतीजन, सुर्खियों में संख्या का स्रोत युद्धरत सरकारों का आंकड़ा ही है। इतिहास सावधानी बरतने की सलाह देता है। 2003 के इराक युद्ध से पहले, पश्चिमी सरकारों ने कहा था कि सद्दाम हुसैन के पास तबाही मचाने वाले हथियारों के जखीरे हैं। दावा वैश्विक मीडिया में दोहराया गया और इसने मध्य-पूर्व से इतर, भारत जैसे देशों में भी राजनयिक विमर्श को आकार दिया था। हमले के बाद, कथित जखीरे कहीं दिखाई नहीं दिए। इससे भी पहले, 1991 के खाड़ी युद्ध के दौरान, टेलीविज़न दर्शकों को 'स्मार्ट बमों' द्वारा इराकी निशानों पर एकदम सटीक प्रहार करती नाटकीय फुटेज दिखाई गई थीं। बाद के विश्लेषणों ने दर्शाया कि इस्तेमाल हथियारों में बहुत कम संख्या प्रिसिजन-गाइडेड अस्त्रों की थी। यह नमूना जाना-पहचाना है: युद्ध में शुरुआती दावे सबसे कम भरोसेमंद होते हैं, और डिजिटल युग में गलत सूचना कहीं ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है।

सरकारें अपने नैरेटिव गढ़ती हैं। ईरानी सरकारी मीडिया मज़बूती व सैन्य कामयाबी पर ज़ोर देता है। वहीं, इस्राइली अधिकारी अपने प्रहारों की सटीकता व असर रेखांकित करते हैं। पश्चिमी नेता हमले निर्णायक बताते हैं, भले ही दीर्घकालीन रणनीतिक परिणाम पक्के न हों। ब्रिटिश प्रधानमंत्री, कीर स्टॉर्मर कुछ सैन्य कार्रवाइयों को 'रक्षात्मक प्रहार' बताते हैं। यह विरोधाभास है, जो ताकत के इस्तेमाल को जायज ठहराता है। इनमें से कोई भी बात बीते वक्त के पत्रकार दिवंगत फिलिप नाइटली को हैरान न करती, जिनकी किताब 'द फर्स्ट कैजुअल्टी' में युद्ध-पत्रकारिता में प्रोपगंडे के लंबे इतिहास की पड़ताल की गई। नाइटली ने कहा कि सरकारें युद्ध के समय हमेशा सूचना प्रबंधन करने की कोशिशें करती हैं: 'मिथ्या-प्रचार के अध्ययन बताते हैं कि यह कितना ताकतवर हथियार हैजविचार को नियंत्रण करना ज़रूरी है'।

समय के साथ वह व्यवस्था कमज़ोर पड़ गयी जो कभी आधिकारिक प्रोपगंडा को चुनौती देती था। बीसवीं सदी के ज़्यादातर वक्त बड़े अखबारों ने मध्य-पूर्व में विदेशी रिपोर्टरों का नेटवर्क कायम कर रखा था। ये रिपोर्टर घूमते थे, गवाहों का इंटरव्यू लेते थे और एक-दूसरे के दावों की तुलना करते थे। वे ज़मीनी जानकारी के बूते आधिकारिक बयानों को चुनौती देने की स्थिति में थे। आज उनमें से कई ब्यूरो गायब हो चुके। कवरेज ज़्यादातर स्टूडियो वार्ता, सोशल-मीडिया फ़ीड और आधिकारिक प्रेस व्यक्तव्यों से आती है, न कि सीधी रिपोर्टिंग से। परिणाम उल्टा है। पहले कभी किसी युद्ध संबंधी आज जितनी जानकारी वास्तविक समय में नहीं मिलती थी। तथापि यह जानना शायद ही कभी इतना मुश्किल रहा कि असल में क्या हो रहा है।

भारत के लिए, ऐसे झगड़ों को स्पष्ट समझने में बहुत कुछ दांव पर लगा है। भारत की नीति लंबे समय से पश्चिम एशिया में रणनीतिक स्वायत्तता की है, और ईरान, इस्राइल और अरब खाड़ी मुल्कों ये व्यावहारिक संबंध हैं। जब किसी युद्ध के बारे में जानकारी प्रोपगंडा, अनुमान और डिजिटली गढ़ी सामग्री से ढक जाए, तो पत्रकारों व नीति निर्माताओं के लिए भी घटनाओं का सही आकलन कठिन हो जाता है।

लेखक पूर्व विदेश सचिव हैं।

ITR फाइल 500/-
Whatsapp पर बनवाएँ
Income Tax फाइल, GST रजिस्ट्रेशन, TDS रिफंड, प्रोजेक्ट रिपोर्ट
CMA DATA, MSME, BALANCE SHEET, फूड लाइसेंस
हमारे Tax Expert आपकी मदद हेतु तैयार है।
सम्पर्क - शेखर गुप्ता 9300755544 - 8878655544
www.onlytds.com

श्रीकंचनपथ
भिलाई-दुर्ग

प्रिंट और डीजिटल मीडिया में
सभी प्रकार के विज्ञापन
के लिए
संपर्क करे
Mob.-:
9303289950
7987166110

प्रमुख खबरें

भिलाई में खाद्य विभाग की टीम ने की व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच

भिलाई। वर्तमान अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों एवं संभावित आपूर्ति दबाव को दृष्टिगत रखते हुए घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक एवं अन्य अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा 12 मार्च 2026 को जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जाँच की गयी। जाँच में दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में दोसा किंग, अग्रसेन चौक से 3 नग, मुकेश फ़ास्ट फूड सेंटर पोलसाय पारा से 2 नग घरेलू गैस सिलेंडर जप्त किया गया। इसके अतिरिक्त भिलाई नगर निगम क्षेत्र में दुर्गा मिष्ठान भंडार से 01 तथा शिव प्रसाद भोजनालय सुपेला से 3 नग घरेलू गैस का व्यवसायिक उपयोग पाए जाने पर जप्त किया गया। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग पर नियंत्रण हेतु जिले में जांच एवं कार्यवाही की प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी तथा भविष्य में भी ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अग्निवीर भर्ती : ऑनलाइन निःशुल्क कोचिंग के लिए आवेदन आमंत्रित

भिलाई। भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु 13 फरवरी 2026 से 01 अप्रैल 2026 तक वेबसाइट www.joinindianarmy.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर द्वारा माह जून में उक्त पंजीकृत अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा (सीसीई) लिया जाना संभावित है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र दुर्ग के उपसंचालक से प्राप्त जानकारी अनुसार वेबसाइट पर आवेदन करने वाले दुर्ग जिले के अभ्यर्थियों को जिला रोजगार कार्यालय दुर्ग द्वारा निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जायेगा। जो आवेदक निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग प्राप्त करना चाहते है वे भारतीय थल सेना में अग्निवीर भर्ती हेतु पंजीयन पश्चात् 20 अप्रैल 2026 तक गूगल लिंक के माध्यम से अथवा निम्न क्यूआर कोड स्कैन कर आवेदन कर सकते है। आवेदक को सेना भर्ती कार्यालय द्वारा जारी पंजीयन क्रमांक एवं व्हाटसप मोबाईल नम्बर का उल्लेखित करना अनिवार्य होगा।

मुख्य न्यायाधीश ने की राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की समीक्षा

दुर्ग। मुख्य न्यायाधीशरमेश सिन्हा द्वारा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत जो 14 मार्च, 2026 को आयोजित की जाएगी, की तैयारियों की समीक्षा हेतु राज्य के सभी प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, परिवार न्यायालयों के न्यायाधीश, स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा श्रम न्यायालयों के न्यायाधीशों की वर्चुअल बैठक छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से ली गई। इस बैठक में माननीय श्री न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू, अध्यक्ष, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति की भी उपस्थिति रही।

साईंस कालेज, दुर्ग की डॉ. अनुराधा सहस्त्रबुध्दे को मिला शैक्षणिक डिवाइस पर आधारित पेटेंट

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। शासकीय विश्वनाथ यादव तामस्कर स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय की मनोविज्ञान विभाग की अतिथि सहायक प्राध्यापक डॉ. अनुराधा सहस्त्रबुध्दे को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा उनके द्वारा प्रस्तुत डिजाइन 'पोर्टेबल एजुकेशन डिवाइस फॉर आर्गेनाइजिंग स्टडी मटेरियल एण्ड असाइन्मेंट' पर पेटेंट स्वीकृत किया गया है। यह पेटेंट भारत सरकार के डिजाइन अधिनियम 2000 तथा डिजाइन नियम 2001 के अध्यायधीन प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किया गया है।

महाविद्यालय के मीडिया प्रभारी डॉ. प्रशांत श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार के महानियंत्रक द्वारा हस्ताक्षरित आदेश के मुताबिक डॉ. अनुराधा सहस्त्रबुध्दे एवं उनके 07 साथी शोधाकर्ताओं यह पटेंट स्वीकृत किया गया। डॉ. अनुराधा सहस्त्रबुध्दे द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार इस एजुकेशनल डिवाइस को विद्यार्थियों, षिक्षाविदों तथा प्रोफेषनलस को पाठ्य

सामग्री, नोट्स तथा हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में असाइन्मेंट आदि के एक्सेस करने के लिए बनाया गया है। यह डिवाइस बहुत ही हल्की, संगठित तथा संग्रहण हेतु विभिन्न खण्डों से युक्त, वायरलेस कनेक्टीविटी से युक्त है।

साईंस कालेज, दुर्ग में अतिथि सहायक प्राध्यापक डॉ. अनुराधा सहस्त्रबुध्दे एवं उनके साथियों द्वारा भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय से पेटेंट स्वीकृत होने पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अजय कुमार सिंह ने बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युवा अतिथि सहायक प्राध्यापक द्वारा इस उपलब्धि से अन्य युवा प्राध्यापकों को भी प्रेरणा मिलेगी तथा महाविद्यालय में पेटेंट प्राप्ति के प्रति रूझान उत्पन्न होगा। उल्लेखनीय है, कि डॉ. अनुराधा सहस्त्रबुध्दे इससे पूर्व अपोलो कॉलेज, अंजोरा, दुर्ग तथा डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, भिलाई में अपनी सेवाएं दे चुकी है। वे श्रीकांत सहस्त्रबुध्दे की पत्नि है। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी साईंस कालेज, दुर्ग के प्राध्यापकों एवं शोधाकर्ताओं द्वारा विभिन्न विषयों पर 15 से अधिक पेटेंट प्राप्त किये जा चुके है, जिनमें देष एवं विदेष दोनों से स्वीकृत पेटेंट शामिल है। डॉ. अनुराधा सहस्त्रबुध्दे की सफलता पर मनोविज्ञान विभाग की अध्यक्ष डॉ. रचिता श्रीवास्तव ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

निगम की बड़ी कार्रवाई, नाली के ऊपर बने 35 से अधिक अवैध निर्माण तोड़े

- **महापौर अलका बाघमार के सख्त निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान**
- **जेसीबी की मदद से हटाए गए अवैध शेड और पक्के निर्माण**
- **शहर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफलगातार जारी रहेगी कार्रवाई**

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए पटरीपार सिकोला भाटा सब्जी मार्केट क्षेत्र में नाली के ऊपर किए गए अवैध निर्माणों को हटाया गया। निगम की टीम ने जेसीबी की मदद से करीब 35 से अधिक दुकानों के बाहर नाली के ऊपर बनाए गए अवैध शेड और पक्के निर्माण को तोड़कर हटाया।

बताया गया कि लंबे समय से इस क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा नाली के ऊपर कब्जा कर पक्के निर्माण कर लिए गए थे, जिससे आवागमन और सफाई व्यवस्था प्रभावित हो रही थी। इस संबंध में नगर निगम द्वारा पहले भी कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन अवैध कब्जाधारियों पर इसका कोई असर नहीं हुआ।

महापौर अलका बाघमार के सख्त निर्देश पर आज अतिक्रमण अधिकारी परमेश्वर कुमार के नेतृत्व में निगम की टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया।

कार्रवाई के दौरान पटरीपार सिकोला भाटा के कई दुकानदारों ने निगम की कार्रवाई को देखते हुए स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए 24 घंटे का समय भी मांगा। इस पर निगम अधिकारियों ने उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी कि तय समय के बाद यदि अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो निगम द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।

महापौर अलका बाघमार ने कहा कि शहर क्षेत्र में सड़क और नालियों के ऊपर अवैध रूप से निर्माण कर व्यवसाय करना किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने शहर के सभी अतिक्रमणकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सड़क या सार्वजनिक स्थानों पर अवैध कब्जा कर व्यवसाय किया जाएगा तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम द्वारा शहर को व्यवस्थित और स्वच्छ बनाने के लिए अवैध अतिक्रमण के खिलाफअभियान लगातार जारी रहेगा और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

'राहत की किश्त' बनी महतारी वंदन योजना की राशि

दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार की 'महतारी वंदन योजना' आज प्रदेश की महिलाओं के लिए आर्थिक सुरक्षा का दूसरा नाम बन गई है, जिसके तहत विवाहित महिलाओं को सालाना ?12,000 की सहायता दी जा रही है। इसी योजना का लाभ उठा रहीं बघेरा की एक साधारण गृहिणी श्रीमती पिंकी यादव की जिंदगी अब पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भर गई है।

घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों के बीच पिंकी को अक्सर छोटी-बड़ी आर्थिक जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब हर महीने उनके खाते में आने वाली राशि ने उनकी चिंताओं को कम कर दिया है। पिंकी बड़े गर्व से बताती हैं कि अब चाहे रसोई के राशन का इंतजाम करना हो या परिवार में अचानक आए स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को संभालना, उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। पिंकी यादव कहती हैं कि यह राशि हर मुश्किल वक्त में उनके लिए 'राहत की किश्त' साबित हो रही है। यह योजना केवल एक वित्तीय मदद नहीं, बल्कि पिंकी जैसी लाखों महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता की नई बुनियाद है।

साईंस कॉलेज दुर्ग के छात्र-छात्राओं को निःशुल्क हेलमेट वितरण

- **वाहन चालकों को यातायत नियमों के पालन हेतु किया जा रहा जागरूक**

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। परिवहन आयुक्त, कार्यालय नवा रायपुर एवं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के दौरान 20 फरवरी 2026 को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय दुर्ग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा साईंस कॉलेज दुर्ग के छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा प्रति जागरूक करते हुए लगभग 30 छात्र-छात्राओं को निः शुल्क हेलमेट वितरण किया गया। साथ ही छात्र-छात्राओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करते हुए शपथ दिलायी गई।

जागरूकता कार्यक्रम में लोगों को हेलमेट पहनने, कार में सीट बेल्ट लगाने, नियमित गति से वाहन लगाने, नेक नागरिक बनने, आपातकालीन सेवा के वाहनों को पास देने, ड्राइविंग लायसेंस बनवाने साथ ही वाहन के सभी दस्तावेज पूर्ण करने हेतु अपील किया जा रहा है, जिससे उम्मीद लगाई जा रही है कि सड़क दुर्घटना में कमी आयेगी। परिवहन विभाग के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री एस. एल. लकड़ा, परिवहन निरीक्षक श्री सनत कुमार जांगड़े, सांख्यिकी अधिकारी श्री सुभाष बंजारे एवं श्री अभिलाष सिंह, परिवहन उप निरीक्षक, तथा सड़क सुरक्षा हेतु भारत केयर कंपनी के श्री बंसत साहू, स्टेट कॉडिनेटर एवं संस्था के प्राचार्य डॉ. ए. के सिंह, वरिष्ठ प्राध्यापक एके खान, एनएसएस अधिकारी प्रो. तरूण साहू, प्रो. सुदेश साहू, एवं प्रो. निखिल देशलहरे उपस्थित रहे।

श्रम विभाग द्वारा विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की राशि का डीबीटी के माध्यम से किया गया वितरण

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के द्वारा श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं की राशि का डीबीटी के माध्यम से वितरण किया गया। विगत दिनों जिले के सिविक सेंटर कला मंदिर भिलाई में 'श्रमिक सम्मेलन' का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मंडल के अंतर्गत संचालित योजनाओं के प्रति जागरूकता लाना और अधिक से अधिक श्रमिकों को लाभान्वित करना था।

योजना के तहत मंडल में पंजीकृत 60 प्रवर्गों के श्रमिकों को जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न सहायता प्रदान की जाती है। इसमें महिला श्रमिकों को 'मिनीमाता महतारी जतन योजना' के अंतर्गत 20 हजार रुपये, 'मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति सहायता' में 1000 से 10,000 रुपये और 'मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता' में 5,000 से 1 लाख रुपये तक की राशि दी जाती है। विदेश में अध्ययन हेतु 50 लाख रुपये का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, अविवाहित पुत्रियों के विवाह व शिक्षा हेतु 20,000 रुपये, मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता, औजार सहायता, सायकल और सिलाई मशीन सहायता (01 नग किट या निर्धारित राशि) प्रदान की जाती है।

मुख्यमंत्री सियान सहायता योजना' के अंतर्गत 59 से 60 आयु वर्ग के श्रमिकों को 20,000 रुपये की राशि दी जाती है। सामान्य मृत्यु पर 1 लाख रुपये, कार्यस्थल पर दुर्घटना मृत्यु पर 5 लाख रुपये तथा दिव्यांगता होने पर 2 लाख 50 हजार रुपये की सहायता का प्रावधान है। कार्यक्रम में जिले के कुल 6,574 श्रमिकों को 3,06,47,343 रुपये तथा संपूर्ण प्रदेश में कुल 9,556 श्रमिकों को 10,42,07,343 रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की गई। साथ ही, 'दीदी ई-रिक्शा सहायता योजना' के तहत 03 हितग्राहियों को ई-रिक्शा की चाबियाँ सौंपी गईं। मंडल के गठन से अब तक कुल 3,48,437 श्रमिकों को 1,10,07,62,606 रुपये की राशि से लाभान्वित किया जा चुका है।

शहर के पात्र हितग्राहियों को मिलेगा पक्का घर, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दुर्ग निगम को 247 बीएलसी आवासों की स्वीकृति

श्रीकंचनपथ न्यूज

दुर्ग। भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत नगर पालिक निगम दुर्ग को बड़ी सौगात मिली है। निगम क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कुल 247 बीएलसी आवासों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इसमें 169 आवास एवं 78 आवास शामिल हैं, जिनकी स्वीकृति राज्य शासन के माध्यम से प्रदान की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं आवासहीन परिवारों को अपने स्वयं के पक्के घर का सपना साकार करने का अवसर मिल रहा है। इसी

कड़ी में नगर निगम दुर्ग क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य शासन द्वारा स्वीकृति जारी की गई है, जिससे अब लाभार्थियों को अपने घर के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी। नगर निगम दुर्ग द्वारा योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण की प्रक्रिया को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा, ताकि पात्र हितग्राहियों को समयबद्ध तरीके से योजना का लाभ मिल सके। निगम प्रशासन द्वारा हितग्राहियों को आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग भी प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने पक्के मकान का निर्माण कर सकें।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को सुरक्षित और स्थायी आवास उपलब्ध कराना है। नगर निगम दुर्ग इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए निरंतर प्रयासरत है, ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ मिल सके। बता दें कि योजना के तहत पात्र हितग्राहियों को अपने आवास निर्माण के लिए नगरीय निकाय से ही भवन अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रति राज्य शहरी विकास अभिकरण को भेजना आवश्यक रहेगा। योजना के अनुसार हितग्राही 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्रफल तक का आवास निर्माण कर सकेंगे।

नगर निगम द्वारा जारी भवन अनुज्ञा में प्रस्तावित आवास का कारपेट क्षेत्रफल दर्ज किया जाएगा और उसी के अनुरूप निर्माण करना अनिवार्य होगा। साथ ही मिशन की मार्गदर्शिका के अनुसार हितग्राहियों का जातिगत आधार पर वर्गीकरण किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। योजना के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को आवास निर्माण के लिए कुल 2.50 लाख रुपये की अनुदान राशि चार किश्तों में प्रदान की जाएगी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर उन्नति महिला सहकारी साख समिति ने रामशीला की कुटिया में किया फल वितरण

- **वृद्धा आश्रम जुनवानी भिलाई में हुआ आयोजन**

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। उन्नति महिला सहकारी साख समिति मर्यादित भिलाई द्वारा अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर रामशीला की कुटिया वृद्धा आश्रम जुनवानी भिलाई में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर फल का वितरण करने के साथ एक नग कूलर वृद्धजनों हेतु आश्रम संचालकों को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उन्नति महिला सहकारी साख समिति के अध्यक्ष कौसर खान, उपाध्यक्ष डॉ मीनाक्षी दुबे, संचालक मंडल एवं सदस्य गण शामिल हुए ।

सर्वप्रथम कार्यक्रम की शुरुआत संस्था के सदस्यों के द्वारा वृद्धा आश्रम में निवास करने वाले वृद्धजनों से परिचय किया गया साख समिति की महिलाओं ने वृद्ध जनों को फल का वितरण करने के साथ उनका आशीर्वाद लिया अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वहां पर निवास करने वाली महिलाओं को महिला दिवस के संबंध की जानकारी भी दिया गया। कार्यक्रम में उन्नति महिला सहकारी समिति की अध्यक्ष कौसर खान द्वारा बुजुर्गों को संबोधित करते हुए कहा कि आप हमारे मार्गदर्शक के रूप में हमेशा हमारे जीवन में रहेंगे आप जैसे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन एवं सहयोग से उन्नति महिला सहकारी साख समिति विगत 14 वर्षों से समाज के जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद करने के साथ महिलाओं को बचत की प्रेरणा दे रहा है। जिससे वे आर्थिक रूप से सक्षम बने आप सभी का आशीर्वाद हम सभी को मिलता रहे। कार्यक्रम में समाजसेवी एवं पत्रकार इस्माईल खान ने उपस्थित वृद्धजनों को शासन द्वारा जारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ उन्हें आवश्यक सहयोग देने की बात कही। संचालक कल्पना निमझे ने प्रेरित गीत प्रस्तुत किया। उन्नति महिला सहकारी साख समिति के संचालक सदस्यों ने वृद्धा आश्रम संचालक से बुजुर्गों को व्यक्तिगत रूप से वृद्ध जनों को एक दिन का खाना खिलाने की इच्छा व्यक्त की जिसे संचालकों ने स्वीकार किया।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के कार्यक्रम को सफल बनाने में साख समिति के उपाध्यक्ष डॉ मीनाक्षी दुबे प्रबंधक, रत्ना चक्रवर्ती, सुनीता कुमारी, समृद्धि ताम्रकार,प्रतिमा पारधी, अवध विश्वकर्मा, रेखा दास, रजनी मेहर, कल्पना निमजे का सहयोग रहा।

कुम्हारी-अहिवारा-बेरला मार्ग के लिए 90.70 करोड़ स्वीकृत

भिलाई। राज्य शासन ने कुम्हारी-अहिवारा-बेरला मुख्य जिला मार्ग के मजबूतीकरण और चौड़ीकरण के लिए 90 करोड़ 69 लाख 87 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इस राशि से 51.40 किमी सड़क का मजबूतीकरण और चौड़ीकरण किया जाएगा। साथ ही 1.40 किमी लंबाई के अंधे मोड़ का पुनर्रेखन भी किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद राज्य शासन ने मंत्रालय से राशि स्वीकृति के संबंध में प्रमुख अभियंता को परिपत्र जारी कर दिया है।

साव ने कार्य में प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियों एवं संपूर्ण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए हैं। किसी भी स्तर पर कार्य की गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर उत्तरदायित्व का निर्धारण करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। लोक निर्माण विभाग ने प्रमुख अभियंता को कार्य की निविदा समय-सीमा में करने, निर्माण कार्य प्राक्कलन व कार्य संपादित करने में मितव्ययिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने निर्माण एजेंसी से अनुबंधित समय-सीमा में काम पूर्ण किया जाना सुनिश्चित कराने को कहा है।

Since 1972
CROWN®-TV
Choice Of Millions
Washing Machine / Cooler
Available All Size

CONTACT :
Atlas Radio Traders (Crown)
Sect.-3, D-48, Ward No. 22
Devendra Nagar, Raipur (C.G.) 492009
Near Akash Gas Agency Line

खास खबर

परम्परा से पहचान तक 'आदि परब-2026' का भव्य आयोजन आज से

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की परिकल्पना और निर्देश पर 13 और 14 मार्च 2026 को नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में 'परम्परा से पहचान तक' - आदि परब - 2026 का भव्य आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति, कला और परंपराओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से 'आदि परब-2026' का भव्य आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की 43 जनजातियों के साथ-साथ दूसरे प्रदेश के जनजाति समुदाय शामिल होंगे भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से आदिम जाति विकास विभाग के अंतर्गत आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दो दिवसीय आयोजन में छत्तीसगढ़ की 43 जनजातियों के साथ-साथ मध्यप्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और झारखंड के जनजातीय समुदाय भी शामिल होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य जनजातीय पहचान, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण तथा पारंपरिक ज्ञान के संवर्धन को बढ़ावा देना है। इस आयोजन में राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के जनजातीय कलाकारों शिल्पकारों तथा जनजातीय समुदायों की सहभागिता होगी।

प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत बच्चों की हुई निःशुल्क हृदय जांच

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार, जिला प्रशासन रायपुर द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए चलाई जा रही योजना प्रोजेक्ट धड़कन के अंतर्गत ज़िले भर में विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभिनव पहल का उद्देश्य है - बच्चों में जन्मजात हृदय रोग की समय रहते पहचान कर उन्हें बेहतर और निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना। कलेक्टर डॉ गौरव सिंह के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन तथा श्री सत्य साई हॉस्पिटल के सहयोग से आज तिल्दा टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र 1 एवं 2 सतभवन में 90 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम ए द्वारा प्राथमिक शाला चुना भट्टी रायपुर में 90 बच्चों की स्क्रीनिंग एवं 01 बच्चा सस्पेक्टेड, अभनपुर टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र 1 एवं 2 खट्टी में 102 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम डी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र सतनामी पारा गुढ़ियारी में 76 बच्चों की स्क्रीनिंग एवं 01 बच्चा सस्पेक्टेड, धरसीवां टीम बी द्वारा शासकीय प्राथमिक शाला एवं मिडिल स्कूल निमोरा में 211 बच्चों की स्क्रीनिंग, आरंग टीम बी द्वारा बाल संदर्भ केंद्र रीवा में 428 बच्चों की स्क्रीनिंग, अर्बन टीम बी द्वारा आंगनबाड़ी केंद्र बैजनाथपारा, छोटापारा एवं सुंदर नगर में 93 बच्चों की स्क्रीनिंग व पूरे जिले में आज कुल 1090 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई।

नेस्ट्स के संयुक्त आयुक्त ने ईएमआरएस का किया निरीक्षण

कोंडागांव। जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (नई दिल्ली) के नेस्ट्स के संयुक्त आयुक्त बिपिन चंद्र रातुरी ने गुरुवार को एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शामपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई भी उपस्थित रहे।

कुपोषण और एनीमिया से जूझने वाली महिला बनी स्वास्थ्य जागरूकता की मिसाल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बेमेतरा जिले के बेरला परियोजना अंतर्गत ग्राम देवरी की निवासी लीला निषाद आज अपने गांव की महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता की प्रेरक मिसाल बन गई हैं। कभी कुपोषण और एनीमिया जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझने वाली लीला का जीवन राष्ट्रीय पोषण माह अभियान से जुड़ने के बाद सकारात्मक रूप से बदल गया।

लीला निषाद का विवाह ग्राम देवरी निवासी भागीरथी निषाद से हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के अभाव में वर्ष 2017 में उन्होंने एक कुपोषित बच्चे को जन्म दिया, जिसकी जन्म के कुछ दिनों बाद मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद उनका स्वास्थ्य भी लगातार गिरता गया और जांच में वे एनीमिया से ग्रस्त पाई गईं।

इसी दौरान गांव की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती अमरौतिन साहू ने उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र में आयोजित राष्ट्रीय पोषण माह के पोषण मेले में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मेले में लीला को संतुलित आहार, हरी सब्जियों, दालों, फ्लों के महत्व तथा आयरन, कैल्शियम और फेलिक एसिड के नियमित सेवन की जानकारी दी गई। इसके बाद लीला ने अपनी जीवनशैली में बदलाव करते हुए संतुलित आहार, नियमित स्वास्थ्य जांच, टीकाकरण और स्वच्छता को अपनाया। गर्भवती होने पर उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सभी सावधानियों का पालन किया, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने एक स्वस्थ बालिका को जन्म दिया। आज लीला निषाद स्वयं स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ-साथ अपने गांव की अन्य महिलाओं को भी पोषण और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक कर रही हैं। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि सही जानकारी और जनभागीदारी से सरकारी अभियान लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना : मुख्यमंत्री साय

- मुख्यमंत्री ने बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का किया शुभारंभ
- 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को मिलेगी 757 करोड़ रुपये से अधिक की राहत
- बिजली उपभोक्ताओं की पीड़ा को दूर करेगी समाधान योजना

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सालय स्थित सभागार से मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने योजना का लाभ लेने वाले उपभोक्ताओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया और अधिक से अधिक लोगों से योजना का लाभ लेने की अपील की। साथ ही मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 2 हजार 931 हितग्राहियों को 8 करोड़ 79 लाख रुपए की सब्सिडी भी अंतरित की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बिजली आज हमारी मूलभूत जरूरतों में शामिल हो चुकी है और इसके बिना जीवन की कल्पना संभव नहीं है। कई परिवार आर्थिक कारणों से समय पर बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाते, जिससे सरचार्ज के कारण बकाया राशि बढ़ जाती है और पूरा भुगतान करना कठिन हो जाता है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने समाधान योजना शुरू की है, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाधान योजना के माध्यम से लंबे समय से बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाने वाले प्रदेश के निम्न एवं मध्यम आय वर्ग तथा कृषि उपभोक्ताओं को राहत देने की पहल की गई है। योजना के तहत प्रदेश के 28 लाख 42 हजार उपभोक्ताओं को कुल 757 करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2014 के बाद देश के लगभग 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जिससे आजादी के बाद से अंधेरे में रहे गांव भी रोशन हुए। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में हमारे अपने संसाधनों से लगभग 30 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और प्रदेशवासियों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल में आर्थिक कठिनाइयों के कारण कई उपभोक्ता बिजली बिल का भुगतान नहीं कर पाए थे, जिससे बकाया राशि बढ़ गई थी। राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं की इस परेशानी को समझते हुए समाधान योजना लागू की है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रति प्रदेश में लोगों की रुचि लगातार बढ़ रही है और अब तक लगभग 36 हजार लोग इससे जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि महिला स्व सहायता समूहों द्वारा सोलर पैनल वेंडर के रूप में कार्य किया जाना एक सकारात्मक पहल है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से बिजली की बचत करने और घरेलू बिजली के अनावश्यक उपयोग से बचने की अपील की।

मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को समाधान योजना के लिए बधाई देते हुए निर्देश दिए कि शिविर लगाकर और व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को समाधान योजना से जोड़ा जाए।

उल्लेखनीय है कि योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं की तीन श्रेणियां निर्धारित की गई हैं, जिनमें 31 मार्च 2023 की स्थिति में निष्क्रिय उपभोक्ता, सक्रिय एकल बत्ती कनेक्शनधारी उपभोक्ता तथा सक्रिय अशासकीय घरेलू एवं अशासकीय कृषि उपभोक्ता शामिल हैं। इन श्रेणियों के उपभोक्ताओं को विद्युत देयक जमा करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में अधिभार की राशि में 100 प्रतिशत छूट तथा मूल बकाया राशि में 75 प्रतिशत तक छूट का प्रावधान किया गया है।

योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को पंजीयन कराना होगा और पंजीयन के समय बकाया राशि का न्यूनतम 10 प्रतिशत भुगतान करना अनिवार्य होगा। शेष राशि का भुगतान किस्तों में किया जा सकेगा और आगामी माह में कोई अधिभार नहीं लगेगा। यह योजना 30 जून 2026 तक प्रभावशील रहेगी। इस अवसर पर रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा, रायपुर नगर निगम महापौर मीनल चौबे, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन अग्रवाल, ऊर्जा विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव सहित बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी और विद्युत उपभोक्ता उपस्थित थे।

महतारी वंदन योजनाः मातृशक्ति के सम्मान और सशक्तिकरण की पहचान

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित महतारी वंदन योजना प्रदेश की लाखों माताओं-बहनों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बन रही है। योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की राशि सीधे उनके बैंक खातों में अंतरित की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिलने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

यह योजना महिलाओं की छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो रही है और परिवार पर उनकी आर्थिक निर्भरता को भी कम कर रही है। योजना से मिलने वाली यह सहायता राशि महिलाओं में आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को मजबूत कर रही है।

इसी कड़ी में कोरबा जिले के शहरी क्षेत्र बुधवारी निवासी श्रीमती हेमलता साहू की कहानी भी प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है। श्रीमती साहू बताती हैं कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य है और कई बार आवश्यक जरूरतों के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता पड़ जाती थी। ऐसे समय में महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि ने उन्हें काफी सहारा दिया है। अब उन्हें अपनी व्यक्तिगत जरूरतों या बच्चों की छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता।

उन्होंने बताया कि वे वर्तमान में अपनी पढ़ाई भी जारी रखे हुए हैं। पढ़ाई के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे योजना से प्राप्त राशि से अपने मोबाइल का रिचार्ज कर अध्ययन जारी रख रही हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और वे अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं।

हेमलता साहू ने योजना के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिससे उनके जैसी महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है।

प्रशिक्षु न्यायाधीश लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका : मुख्यमंत्री

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से विधानसभा स्थित उनके कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी, बिलासपुर के प्रशिक्षु न्यायाधीशों ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री साय ने सभी प्रशिक्षु न्यायाधीशों को न्यायिक सेवा में चयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण और सशक्त स्तंभ है। आने वाले समय में आप सभी के कंधों पर समाज और न्याय व्यवस्था से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आप सभी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहते हुए इन जिम्मेदारियों का सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि न्यायपालिका आमजन के अधिकारों की रक्षा और न्याय व्यवस्था में जनता के विश्वास को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है।

इस अवसर पर विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सांवत, छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी की संचालक निधि शर्मा तिवारी सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

बस्तर और सरगुजा में औषधीय पौधों की योजनाओं का होगा विस्तार

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड की समीक्षा बैठक का आयोजन 12 मार्च को बोर्ड कार्यालय के सभागार में किया गया। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने की।

बैठक में बोर्ड के अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा कि वन मंत्री केदार कश्यप के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड लगातार बेहतर कार्य कर रहा है। उन्होंने बैठक में निर्देश दिए कि बोर्ड और शासन की योजनाओं का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंचाया जाए। विशेष रूप से बस्तर और सरगुजा संभाग में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक ठोस रोडमैप तैयार किया जाए। उन्होंने स्थानीय वैद्यों के स्थायी पंजीकरण के लिए भी आवश्यक प्रयास करने को कहा।

बोर्ड के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अंजय शुक्ला ने बैठक में कहा कि औषधीय पौधों का क्षेत्र अपार संभावनाओं से भरा है। उन्होंने कहा कि हमारा सपना है कि बस्तर औषधीय पौधों के माध्यम से दुनिया के समृद्ध क्षेत्रों में शामिल हो। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे.ए.सी.एस. राव ने बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं और गतिविधियों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें वन क्षेत्रों में औषधीय पौधों का रोपण, औषधीय पौधों की खेती (कृषिकरण) तथा विभिन्न नवाचार कार्यों की जानकारी दी गई।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जे.ए.सी.एस. राव ने आश्वस्त किया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्देशानुसार जल्द ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर बस्तर क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने का कार्य शुरू किया जाएगा। प्रारंभिक चरण में बस्तर क्षेत्र में पहले से लगाए गए पाम और नीलगिरी के प्लांटेशन में औषधीय पौधों की मल्टी- क्रॉपिंग के माध्यम से कार्य किया जाएगा।

बैठक में नारायण संकल्प फाउंडेशन रायपुर की सीमा गुप्ता, एन.डी. मेमोरियल फाउंडेशन दुर्ग के शालीभद्र मुथा, क्रिस्टल एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी की रीनू छाबड़ा सहित बोर्ड की योजनाओं से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। इसके अलावा बोर्ड के तकनीकी सलाहकार और कर्मचारी भी बैठक में शामिल हुए।

बिहान परियोजना से मिला आत्मनिर्भरता का संबल

सिलाई सेंटर और मिनी राइस मिल से प्रतिमाह 20 से 30 हजार रुपये की आय, मुख्यमंत्री साय ने किया सम्मानित

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। मुंगेली जिले के पथरिया विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम गोइन्द्री की निवासी शांतामणी गेंदले ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और संघर्ष से सफलता की मिसाल बन गई हैं। कभी आर्थिक तंगी और कर्ज के बोझ से जूझने वाली शांतामणी ने अपनी मेहनत, आत्मविश्वास तथा स्व-सहायता समूह के सहयोग से न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया, बल्कि अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित किया है।

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) को बिहान परियोजना के नाम से संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को स्व-सहायता समूहों से जोड़कर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसी परियोजना से जुड़कर शांतामणी गेंदले ने भी अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की नई शुरुआत की।

शांतामणी गेंदले संस्कार महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं और ग्राम संगठन तथा संकुल स्तरीय संगठन (सीएलएफ) में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वर्तमान में वे एफएलसीआरपी (वित्तीय साक्षरता सामुदायिक संसाधन व्यक्ति) के रूप में भी कार्य करते हुए ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। उनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर रायपुर में आयोजित लखपति संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया।

कुछ वर्ष पूर्व तक शांतामणी का जीवन अत्यंत संघर्षपूर्ण था। सीमित आय और आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण उन्हें छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए भी साहूकारों से ऋण लेना पड़ता था। ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था, जिससे परिवार का भरण-पोषण करना भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन तब आया जब वे बिहान परियोजना के अंतर्गत संचालित संस्कार महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ीं। समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने नियमित बचत की आदत विकसित की और वित्तीय प्रबंधन की बारीकियों को समझा। समूह के माध्यम से उन्हें रिवॉल्विंग फंड (आरएफ) और सामुदायिक निवेश कोष (सीआईएफ) की सहायता प्राप्त हुई। इसके साथ ही बैंक लिंकेज तथा संकुल स्तरीय संगठन के माध्यम से उन्हें ऋण सुविधा भी मिली, जिससे उन्होंने आजीविका के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया।

प्राप्त ऋण राशि का उपयोग उन्होंने आय बढ़ाने वाले कार्यों में निवेश के रूप में किया। उन्होंने अपने गांव में सिलाई सेंटर प्रारंभ किया, जहां वे सिलाई का कार्य करती हैं। इसके साथ ही उन्होंने मिनी राइस मिल की स्थापना कर गांव में ही धान कुटाई की सुविधा उपलब्ध कराई। इन प्रयासों के परिणामस्वरूप आज वे प्रतिमाह लगभग 20 हजार से 30 हजार रुपये की आय अर्जित कर रही हैं, जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार आया है।

शांतामणी की उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं हैं। एफएलसीआरपी के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने 60 से अधिक स्व-सहायता समूहों को लगभग 1 करोड़ 38 लाख रुपये की ऋण राशि उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 30 समूहों को रिवॉल्विंग फंड दिलाने में सहयोग किया तथा 80 से अधिक समूहों को वित्तीय साक्षरता प्रदान कर बैंकिंग और वित्तीय लेन-देन के प्रति जागरूक बनाया।

बस्तर की बेटी हेमलता बनीं उद्यमिता की मिसाल

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम माड़पाल की रहने वाली हेमलता कश्यप की कहानी आज उन तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा है जो संसाधनों के अभाव में अपने सपनों को दम तोड़ने देते हैं। जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव में रहने वाली हेमलता के परिवार की आर्थिक स्थिति कभी काफी चुनौतीपूर्ण थी। महज एक एकड़ कृषि भूमि और छह सदस्यों वाले बड़े परिवार की जिम्मेदारी के बीच 12वीं पास हेमलता हमेशा से अपने पिता पाकलु कश्यप का हाथ बंटाना चाहती थीं। उनके मन में कुछ कर गुजरने की सोच तो थी, लेकिन सही दिशा और पूंजी का अभाव आड़े आ रहा था।

इसी दौरान हेमलता की नजर अखबार में छपी मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना पर पड़ी। उन्होंने इसे अपनी किस्मत बदलने के अवसर के रूप में देखा और अपने पिता के साथ जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र जगदलपुर के कार्यालय पहुंचीं। वहां अधिकारियों से मिली विस्तृत जानकारी ने उनके भीतर किराना दुकान शुरू करने का उत्साह जगा दिया। उनके घर की स्थिति भी व्यापार के अनुकूल थी, क्योंकि उनका मकान मुख्य मार्ग पर स्थित था। सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव में किराने की दुकान न होने के कारण ग्रामीणों को छोटी-छोटी जरूरतों के लिए 10 किलोमीटर दूर नगरनार जाना पड़ता था। ग्रामीणों की इस असुविधा को दूर करने और आत्मनिर्भर बनने के संकल्प के साथ हेमलता ने ऋण के लिए आवेदन किया। दिसंबर 2022 में माड़पाल स्थित छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक की शाखा से उन्हें 2 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हुआ, जिसमें शासन की ओर से 50 हजार रुपये का अनुदान भी मिला। इस राशि से उन्होंने मेसर्स कश्यप किराना स्टोर्स की नींव रखी। व्यवसाय शुरू होते ही उनकी मेहनत रंग लाने लगी और आज उनकी दुकान पर प्रतिदिन हो रही बिक्री के कारण उन्हें हर दिन 500 से 700 रुपये की शुद्ध आमदनी प्राप्त होती है। हेमलता ने महज तीन वर्षों के भीतर अपने ऋण की पूरी राशि का भुगतान कर दिया है और अब उनका वार्षिक टर्नओवर 2 से 3 लाख रुपये के बीच है। आज हेमलता न केवल अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बन चुकी हैं, बल्कि अपनी सफलता से बेहद खुश और संतुष्ट भी हैं।

क्या 'धुरंधर 2' में यामी गौतम भी आएंगी नजर?

फिल्म 'धुरंधर 2' का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म की रिलीज को चंद दिन बाकी हैं। इससे पहले खबर है कि इस फिल्म में यामी गौतम भी नजर आ सकती हैं।

फिल्म में एक्ट्रेस के कैमियो से आएगा ट्विस्ट

रणवीर सिंह अभिनीत ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की दूसरी कड़ी यानी 'धुरंधर 2' 19 मार्च को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। आदित्य धर निर्देशित इस फिल्म को लेकर दर्शक बेहद उत्साहित हैं। इस उत्साह की एक और वजह मिल गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में यामी गौतम भी नजर आएंगी।

हॉस्पिटल में कैमियो की अटकल

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रणवीर सिंह की फिल्म में यामी एक स्पेशल रोल में नजर आएंगी। यामी 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' और 'धुरंधर 2' के बीच एक कड़ी होंगी। बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड की रिपोर्ट के मुताबिक यामी गौतम का स्पेशल अपीयरेंस फिल्म में एक अहम ट्विस्ट लेकर आएगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनका कैमियो हॉस्पिटल में होगा। हालांकि, अभी तक मेकर्स की तरफ से इसे लेकर कोई पुष्टि नहीं की गई है।

क्या 'उरी' वाला रोल निभा सकती हैं?

इस बीच पुरानी रिपोर्ट में कहा गया है कि यामी फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' के अपने किरदार को दोहरा सकती हैं। बता दें कि इस फिल्म में उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का किरदार निभाया था, जो आर्म्ड फोर्सेज के साथ मिलकर काम करती है। हालांकि, फिलहाल स्पष्ट नहीं है कि क्या हकीकत है। यामी फिल्म में नजर आएंगी या नहीं और क्या किरदार निभाएंगी, यह फिल्म की रिलीज के साथ ही स्पष्ट हो पाएगा।

फिल्म में रणवीर सिंह की वापसी

रणवीर सिंह फिर से लयारी के राजा (हमजा अली मजारी उर्फ जसकिरत सिंह रंगी) के रोल में नजर आएंगे। ट्रेलर में एक्टर का लुक और ताकतवर अंदाज देख दर्शक हैरान हैं। उन्होंने इस किरदार को और मजबूत, भारी और असरदार बनाया है। फिल्म में रणवीर सिंह के साथ आर. माधवन, संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन के साथ कुछ और भी कलाकार नजर आएंगे।

यह फिल्म 19 मार्च 2026 को थिएटर्स में आएगी (ईद, गुड़ी पड़वा और उगादी के मौके पर)। हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में भी रिलीज होगी।

एक्ट्रेस पूर्णा की फिल्म डार्क नाइट की रिलीज़ डेट अनाउंस

डार्क नाइट ने अपनी रिलीज़ अनाउंस कर दी है। एक्ट्रेस पूर्णा डार्क नाइट नाम की एक इमोशनल एंटरटेनर में काम कर रही हैं। लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ अनाउंस कर दी है। फिल्म 13 मार्च 2026 को रिलीज़ होगी।

जीआर. आदित्य के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में त्रिगुन, वीरधार्थ, सुभाश्री रायगुरु अहम रोल में हैं। मिस्किन इसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं और इसे पटलोला वेंकट रेड्डी ने पी19 स्टूडियोज़ के बैनर तले प्रेजेंट किया है। फिल्म को सुरेश रेड्डी कोव्वुरी ने प्रोड्यूस किया है।

पूर्णा ने हेमा का किरदार निभाया है, जो कहानी को आगे बढ़ाने वाला एक अहम रोल है। कहानी चार मेन किरदारों की ज़िंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनके इमोशन, राज़ और झगड़े धीरे-धीरे सामने आते हैं, जिससे एक टेंशन वाली और दिलचस्प कहानी बनती है।

एक्टर त्रिगुण, जिन्हें अदित अरुण के नाम से भी जाना जाता है, रोशन के रोल में हैं, जबकि विदार्थ एलेक्स का रोल निभा रहे हैं। सुभाश्री रायगुरु सोफिया के रोल में हैं, जो फिल्म की मेन कहानी में और गहराई जोड़ती हैं। फिल्म के प्रमोशन ने मूवी लवर्स के बीच दिलचस्पी पैदा की।

भूत बंगला का नया पोस्टर आया सामने, उल्टे लटके दिखे अक्षय

अक्षय कुमार ने अपने करियर में कई हिट हॉरर-कॉमेडी फिल्में दी हैं। अब उनकी फिल्म भूत बंगला भी जल्द सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हाल ही में मेकर्स ने इसका नया पोस्टर शेयर करते हुए इसकी टीजर रिलीज डेट भी शेयर की है।

अक्षय ने फिल्म का नया मोशन पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकांउट पर साझा किया। इस पोस्टर में एक्टर पेड़ से उल्टे लटके हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उनके दूसरी तरफ एक चमगादड़ भी लटका हुआ है।

पीछे अंधेरा और घना जंगल नजर आ रहा है। वहीं एक पुरानी सी हवेली भी दिखाई दे रही है। क्योंकि यह एक हॉरर-कॉमेडी है ऐसे में अक्षय कॉमिक अंदाज में नजर आ रहे हैं।

अक्षय कुमार के इस सोशल मीडिया पोस्ट के मुताबिक फिल्म भूत बंगला का टीजर रिलीज होगा। अक्षय ने अपनी इस पोस्ट को कैप्शन देते हुए लिखा- जब तक फिल्म का टीजर नहीं आ जाता, तब तक इसी तरह लटका हुआ हूं। 'भूत बंगला' का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वामिका गब्बी, तब्बू और परेश रावल भी मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके साथ ही फिल्म में राजपाल यादव और मिथिला पालकर भी अहम किरदारों में होगें।

बॉयफ्रेंड के लिए घर छोड़कर केरल भागीं वायरल गर्ल मोनालिसा, बोलीं- पिता बना रहे थे दबाव

प्रयागराज महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों को लेकर चर्चा में आईं वायरल गर्ल मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से अचानक शादी करके हर किसी को चौंका दिया है। परिवार के विरोध जताने पर उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है।

प्रयागराज महाकुंभ मेले की खूबसूरत आंखों वाली माला विक्रेता मोनालिसा याद हैं? अपनी खूबसूरती को लेकर सोशल मीडिया पर वे रातोंरात लोकप्रिय हो गई थीं, जिसके बाद उन्हें महाकुंभ की 'वायरल गर्ल' के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिए हैं। फिलहाल मोनालिसा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड के साथ शादी रचा ली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोनालिसा के परिवार ने इस शादी का विरोध किया है।

इसके बाद वे थाने पहुंची हैं और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मोनालिसा ने सुरक्षा के लिए केरल में पनाह ली है। उनके अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी करने पर निर्देशक सनोज मिश्रा ने इसे लव जिहाद करार दिया है। वहीं उनके गुरु और घरवालों ने भी इस मामले पर हैरानी जताई है।

परिवार के विरोध के बाद केरल में ली शरण

मोनालिसा भोसले ने तिरुवनंतपुरम के थंपनूर पुलिस स्टेशन में शरण ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वायरल गर्ल अपने प्रेमी फरमान खान के साथ थाने पहुंचीं। उन्होंने परिवारों के विरोध करने के बाद केरल में सुरक्षित जगह के तौर पर शरण ली। मोनालिस और फरहान का रिलेशन करीब डेढ़ साल पहले फेसबुक पर बातचीत के जरिए शुरू हुआ था।

अन्य युवक से शादी का था दबाव

मोनालिसा मूल रूप से मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के महेश्वर की रहने वाली हैं। वहीं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके प्रेमी फरमान खान महाराष्ट्र के निवासी हैं। मोनी ने पुलिस को बताया कि उनके पिता इस शादी के खिलाफ हैं और किसी अन्य युवक से शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। लेकिन, वे फरमान के साथ ही रहना चाहती हैं। मोनालिसा अपने बॉयफ्रेंड के साथ स्टेशन पहुंची।

मोनालिसा के पिता को बुलाया गया थाने

दरअसल, मोनालिसा एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में पूवर में आई हुई थीं, इसी दौरान वे थाने पहुंचीं। मोनी की शिकायत के बाद उनके पिता जय सिंह भोसले को थंपनूर पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पुलिस ने परिवार को समझाया कि चूंकि मोनी 18 साल की है, इसलिए उसे यह तय करने का कानूनी अधिकार है कि वह किसके साथ रहना चाहती है। बाद में महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली गईं।

कमर दर्द से राहत और बेहतर पाचन के लिए रोज करें उत्थित पार्श्वकोणासन

रोजाना योगाभ्यास स्वस्थ जीवनशैली अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। कई लोग आम योगासन के बारे में तो जानते हैं, लेकिन उत्थित पार्श्वकोणासन के बारे में कम ही जानते हैं।

इस आसन के नियमित अभ्यास से शरीर को कई तरह के शारीरिक लाभ मिल सकते हैं। उत्थित पार्श्वकोणासन एक संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ विस्तारित पार्श्व कोण मुद्रा है। यह खड़े होकर किया जाने वाला योगासन है, जो तत्वों को मिलाकर शरीर के साइड भाग को खोलता है। इसके नियमित अभ्यास से शरीर के दोनों तरफ में गहरा खिंचाव आता है, जिससे कमर दर्द में राहत मिलती है और रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है। योग विशेषज्ञों का मानना है कि रोजाना 30-60 सेकंड तक इसके अभ्यास से जीवनशैली बेहतर हो सकती है। हालांकि, इसके साथ संतुलित आहार भी लेना चाहिए।

इसको करना बेहद आसान है। इसके लिए सबसे पहले योगा मैट पर दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर फैला लें। अब दाहिने पैर के पंजे को बाहर की तरफ घुटने से धीरे-धीरे मोड़ें और उसी मुद्रा में नीचे की ओर बैठें। फिर अपने दाएं हाथ को दाएं पैर के पास जमीन पर रखें और बाएं हाथ को ऊपर की ओर सीधा 90 डिग्री के एंगल में रखने की कोशिश करें। कुछ देर इसी मुद्रा में रहने की कोशिश करें, फिर धीरे-धीरे सामान्य हो जाएं। हालांकि, शुरुआती अभ्यासकर्ताओं को इसको करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे आदत हो जाएगी और शरीर खुलने लगेगा।

आयुष मंत्रालय ने इसको करने के फायदे पर अहम प्रकाश डाला है। उनके अनुसार, यह एक खड़ी मुद्रा वाला योगासन है, जो पेट के अंगों की मालिश करता है, पाचन में सुधार लाता है, और पैरों व रीढ़ को मजबूत करता है। इसके अलावा, शरीर में लचीलापन भी बढ़ता है और रीढ़ की हड्डी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

वहीं, इससे दिमाग को शांति भी मिलती है और मानसिक तनाव से भी दूरी बनी रहती है।

इसके नियमित अभ्यास से शरीर को कई तरह के लाभ मिल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में इसको किसी योग विशेषज्ञ की निगरानी में ही करें, और अगर आपको कोई गंभीर चोट, माइग्रेन, या हाल ही में कोई सर्जरी हुई है, तो करने से पहले डॉक्टर या योग विशेषज्ञ से सलाह लें।

केला एक प्रकृति का सुपरफूड, जो हर उम्र में रखे सेहत का ख्याल

केला भारत के सबसे प्राचीन और पोषक फलों में से एक माना जाता है। यह सिर्फ स्वादिष्ट फल नहीं है, बल्कि एक ऊर्जा-पोषण-उपचार त्रिवेणी है। आयुर्वेद के अनुसार, केला मधुर, गुरु, शीतल, बल्य, पित्त-शामक, वात-नाशक और ओज-वर्धक होता है, इसलिए इसे सर्वगुण संपन्न फल भी कहा जाता है।

यह सस्ता, आसानी से उपलब्ध और हर आयु के लिए सुरक्षित है। खासकर बच्चों, छात्रों, एथलीट्स, बुजुर्गों, कमजोर व्यक्तियों, एनीमिया और पाचन कमजोरियों वाले लोगों के लिए केला तुरंत ऊर्जा देने वाला सुपरफूड है। केला खाने के कई खास तरीके हैं। अगर हल्की गैस, कब्ज या अपच हो तो केले पर चुटकीभर काला नमक डालकर खाने से आमपित्त शांत होता है और अग्नि संतुलित रहती है। थकावट या कमजोरी में गुनगुना दूध और केला अच्छा ऑप्शन है। यह मांसपेशियों के लिए पोषक माना जाता है। पेट की जलन या अल्सर में थोड़ी मिश्री के साथ केला खाना अच्छा होता है। कमजोरी महसूस हो तो केला और शहद का सेवन करें, यह शरीर में ओज बढ़ाता है और इम्युनिटी मजबूत करता है।

नींद न आने की समस्या हो तो केला और गर्म दूध बेहद फायदेमंद है, क्योंकि इसमें ट्रिप्टोफैन और मेलाटोनिन मिलकर अच्छी नींद लाते हैं।

यह महिलाओं व छात्रों के लिए विशेष लाभकारी है। एथलीट्स के लिए केला काफी फायदेमंद होता है और थकान तुरंत दूर करता है। त्वचा के लिए पका केला और दही का फेस पैक बनाकर लगाने से नमी, निखार और कोमलता आती है।

आंतों की सफाई के लिए सुबह खाली पेट 1-2 केले खाने से डिटॉक्स होता है। केला गर्भवती महिलाओं के लिए भी गर्भ-पोषण फल माना गया है। यह शरीर में प्राकृतिक रूप से सेरोटोनिन बढ़ाता है, जिससे मूड अच्छा रहता है। केला हर उम्र और हर परिस्थिति में प्राकृतिक सुपरफूड है, लेकिन रात में देर से खाने या अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से बचना चाहिए। इससे भारीपन महसूस होता है।

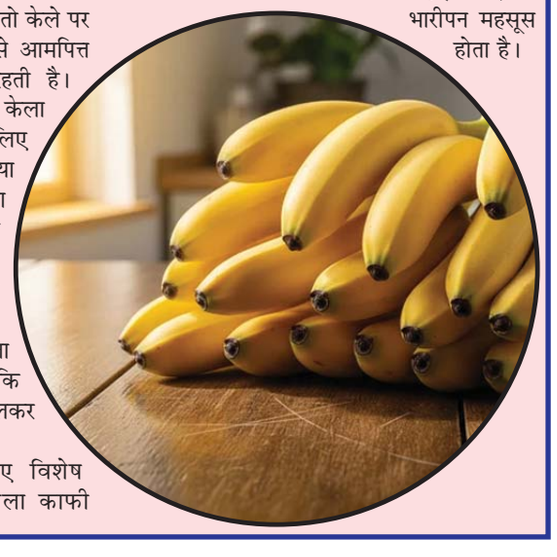

खास खबर

अब 'कर्मचारी चयन मंडल' से सँवरेगा युवाओं का भविष्य : भाजपा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता देवलाल ठाकुर ने विष्णुदेव साय सरकार द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) को भंग कर 'कर्मचारी चयन मंडल' के गठन के निर्णय का स्वागत करते हुए इसे छत्तीसगढ़ के युवाओं के हित में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम बताया है। श्री ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने सत्ता संभालते ही युवाओं से किया अपना वादा निभाया है। व्यापम की पुरानी व्यवस्था में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए यह बड़ा प्रशासनिक सुधार किया गया है।भाजपा प्रदेश प्रवक्ता श्री ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचारमुक्त पारदर्शी व्यवस्था कायम कर प्रदेश की भाजपा सरकार ने अब भृत्य से लेकर बाबू, सिपाही और राजपत्रित अधिकारियों तक की सभी भर्तियाँ एक ही छत के नीचे 'कर्मचारी चयन मंडल' द्वारा करने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। इसका मुख्य उद्देश्य परीक्षाओं का समयबद्ध आयोजन और परिणामों की त्वरित घोषणा सुनिश्चित करना है, ताकि युवाओं का कीमती समय बर्बाद न हो। श्री ठाकुर ने कहा कि यह युवाओं को बड़ी सौगात है। पिछली सरकार के समय परीक्षाओं में जो अनिश्चितता और अव्यवस्था का माहौल था, उसे साय सरकार ने जड़ से खत्म करने का निर्णय लिया है।

17 मार्च को कांग्रेस करेगी विधानसभा घेराव, विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रदर्शन

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 17 मार्च को विधानसभा घेराव करने का ऐलान किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि मनरेगा से जुड़े मुद्दों सहित प्रदेश के विभिन्न जनसरोकारों को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महासचिव सचिन पायलट सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम लोग शामिल होंगे।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बताया कि विधानसभा घेराव की तैयारियों के लिए जिलावार और विधानसभा क्षेत्रवार प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का आयोजन किया गया है, वहीं जिलों में भी लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं।उन्होंने कहा कि मनरेगा से जुड़े विषयों, बिजली दरों, धान खरीदी, किसानों से जुड़े मुद्दों और महंगाई जैसे विषयों को लेकर कांग्रेस यह कार्यक्रम करेगी। पार्टी का कहना है कि इन मुद्दों को लेकर जनता की आवाज उठाने के उद्देश्य से विधानसभा घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के अनुसार मनरेगा योजना से जुड़े बदलावों और बजट से संबंधित पहलुओं पर भी चर्चा की जा रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि रोजगार और मजदूरों से जुड़े मुद्दों पर जनजागरूकता लाने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।इस कार्यक्रम में प्रदेशभर से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है।

वनांचल ग्राम बांधा में 58 परिवारों को मिला भूमि का मालिकाना हक

श्रीकंचनपथ समाचार

कवर्धा। शासन की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को उनके मकान और भूमि का कानूनी अधिकार प्रदान करने के उद्देश्य से जिले में अधिकार अभिलेखों का वितरण किया जा रहा है। इसी कड़ी में बोड़ला विकासखंड के वनांचल ग्राम बांधा में आज स्वामित्व योजना के तहत 58 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख वितरित किए गए। इसके अंतर्गत ग्राम बांधा के 29, झंडी के 18 और केसदा के 11 हितग्राहियों को अधिकार अभिलेख प्रदान किया गया।

इस अवसर पर कलेक्टर गोपाल वर्मा, जनपद पंचायत उपाध्यक्ष नंद श्रीवास, जिला पंचायत सदस्य लोकचंद साहू सहित, नितेश अग्रवाल, डिप्टी कलेक्टर आर बी देवांगन, तहसीलदार हुलेश्वर पटेल, सरपंच गिरजा रामदयाल साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कहा कि स्वामित्व योजना ग्रामीण लोगों को उनके मकान और भूमि का कानूनी अधिकार देने की एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों को उनके घरों का मालिकाना हक और प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन दस्तावेजों के मिलने से ग्रामीण अब बैंकों से आसानी से ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आय और आत्मनिर्भरता में वृद्धि होगी।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए लगभग 11 हजार 763 करोड़ रुपये की अनुदान मांगें पारित

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए 11 हजार 762 करोड़ 53 लाख रूपए की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं है। इनमें महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए 10,162 करोड़ 53 लाख रूपए तथा समाज कल्याण विभाग के लिए 1600 करोड़ रूपए से अधिक का बजट प्रावधान किया गया है।

मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने सदन में चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार मातृशक्ति के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का प्रभावी संचालन कर रही है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक है। यह योजना राज्य की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल साबित हुई है। इसके तहत प्रदेश की लगभग 70 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। अब तक 25 किश्तों में 14 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्रदान की जा चुकी है। इससे महिलाओं के जीवन में आर्थिक मजबूती के साथ आत्मनिर्भरता को भी बढ़ावा मिला है और उनके जीवन में स्वावलंबन लाने का काम किया है।

श्रीमती राजवाड़े ने सदन में कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य तथा पोषण को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 120 करोड़ रुपये तथा मिशन वात्सल्य योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन के लिए 800 करोड़ रुपये तथा पूरक पोषण आहार के लिए 650 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन और आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य और पोषण के लिए 'किशोरी बालिका योजना' के लिए 40 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही छात्राओं की स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए 'शुचिता योजना' के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गारंटी को पूरा करने राज्य सरकार बेटियों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखते हुए 'रानी दुर्गावती योजना' प्रारंभ करने जा रही है। इस योजना के तहत बेटी के 18 वर्ष पूर्ण होने पर उन्हें 1.5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए इस वर्ष के बजट में 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा पोषण अभियान के संचालन के लिए 125 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री सामूहिक कन्या विवाह योजना के लिए 40 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान रखा गया है। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि हमारी सरकार महिलाओं की सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास और चाइल्ड हेल्पलाइन जैसी योजनाओं के संचालन के लिए भी बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया गया है। महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। सदन को जानकारी देते हुए श्रीमती राजवाड़े ने बताया कि समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में लगभग 59 प्रतिशत अधिक है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रदेश में लगभग 21 लाख 76 हजार हितग्राहियों को पेंशन का लाभ डीबीटी के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके लिए 1402 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों के देखभाल और सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए राज्य में सियान गुड़ी डे-केयर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वृद्धाश्रमों के संचालन के लिए 6 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए 20 करोड़ रुपये तथा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए विशेष विद्यालयों के संचालन, कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण वितरण तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिए भी बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

दूरस्थ गांव में शिक्षा का उत्साह, कुचारास स्कूल में कलेक्टर-सीईओ बने स्टूडेंट

श्रीकंचनपथ समाचार

सुकमा। जिले के दूरस्थ नक्सल प्रभावित क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर अमित कुमार और जिला पंचायत सीईओ मुकुन्द ठाकुर ने ग्राम कुचारास के स्कूल का दौरा किया। अधिकारियों ने बच्चों के बीच बैठकर उनकी पढ़ाई-लिखाई की जानकारी ली और शिक्षा की गुणवत्ता का जायजा लिया।इस दौरान स्कूल में एक अनोखा और प्रेरक दृश्य देखने को मिला।

कलेक्टर और जिला सीईओ स्वयं छात्र बनकर बच्चों के साथ बैठ गए और बच्चों ने उन्हें गिनती और मात्रा पढ़ाकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। बच्चों के आत्मविश्वास और पढ़ाई के स्तर से कलेक्टर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने बच्चों को पेन और चॉकलेट वितरित कर उनका उत्साहवर्धन किया।दौरे के दौरान अधिकारियों ने ग्राम मारोकी में भी बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों से पूछा कि बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। इस पर किसी बच्चे ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई तो किसी ने शिक्षक बनकर समाज की सेवा करने की बात कही। बच्चों के सपनों और आत्मविश्वास को देखकर कलेक्टर ने उन्हें खूब प्रोत्साहित किया।आँगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छोटे बच्चों के साथ रोचक गतिविधि भी कराई।

उन्होंने बच्चों को अलग-अलग तस्वीरें दिखाकर पूछा कि यह क्या नन्हे बच्चों ने बड़ी मासूमियत के साथ गोभी और प्याज पहचानकर जवाब दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग खुश हो गए।कलेक्टर ने कहा कि दूरस्थ और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को भी बेहतर शिक्षा और सुविधाएँ मिलना उनका अधिकार है। प्रशासन इस दिशा में पूरी गंभीरता से काम कर रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चों की पढ़ाई के लिए हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

आमाकोनी सबस्टेशन की क्षमता बढ़ी, 19 गांवों को मिलेगी लो-वोल्टेज और ओवरलोडिंग से राहत

श्रीकंचनपथ समाचार

महासमुंद। क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों के लिए बिजली से जुड़ी समस्याओं में अब बड़ी राहत मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से आमाकोनी 33/11 केवी सबस्टेशन की क्षमता में वृद्धि की गई है।

विद्युत विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में सबस्टेशन के ट्रांसफार्मर का अपग्रेडेशन किया गया, जिसके तहत इसकी क्षमता 3.15 एमवीए से बढ़ाकर 5 एमवीए कर दी गई है। ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने से क्षेत्र के 19 गांवों को सीधा लाभ मिलेगा। इन गांवों में लंबे समय से बिजली की बढ़ती मांग के कारण लो-वोल्टेज और ओवरलोडिंग की समस्या बनी हुई थी। विद्युत विभाग के अनुसार सबस्टेशन की क्षमता बढ़ने से अब क्षेत्र में होने वाली ओवरलोडिंग और लो-वोल्टेज की समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। खासकर कृषि सीजन के दौरान किसानों को बार-बार होने वाली ट्रिपिंग की समस्या से भी राहत मिलेगी, जिससे सिंचाई कार्य सुचारू रूप से हो सकेगा। इस कार्य के दौरान अधीक्षण अभियंता वाई.के. मनहर, कार्यपालन अभियंता पी.आर. वर्मा, एसटीएम कार्यपालन यंत्री आर.के. चौहान तथा प्रोजेक्ट कार्यपालन यंत्री महेश नायक सहित विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौजूद रहे और उन्होंने इस पहल का स्वागत करते हुए विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

मैनुअल स्केवेंजर्स हेतु राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक संपन्न

श्रीकंचनपथ समाचार

रायपुर। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आज छत्तीसगढ़ शासन के अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध तथा उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति की बैठक मंत्रालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित हुई।

बैठक में भारसाधक सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग बसव राजू, आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग डॉ. सारांश मित्तर, अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग वी.पी. तिर्की, संयुक्त सचिव अनुपम त्रिवेदी, अपर संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एन. बुलीवाल, द.पू.म.रे. से मुख्य स्वास्थ्य निरीक्षक रणजीत सुमन, सहायक निदेशक, जनगणना निदेशालय एम.के. महलांगे, एनजीओ से सुनिता कुर्रे, समुदाय की महिला एवं पुरूष प्रतिनिधि क्रमशः उत्तरा प्रहरे एवं राजपाल कसेर सहित विभाग के अपर संचालक जितेन्द्र गुप्ता, उपायुक्त विश्वनाथ रेडडी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने कहा कि शासन द्वारा राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति के पुनर्गठन के बाद यह पहली बैठक है उन्होंने बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के परिपालन में गाईडलाइन अनुसार प्रदेश के समस्त जिलों में मैनुअल स्केवेंजर्स रिसर्वे करवाया गया जिसमें सभी जिला कलेक्टर द्वारा मैनुअल स्केवेंजर्स मुक्त का प्रमाण पत्र दिया गया है जो कि प्रदेश के लिए बहुत ही सम्मान एवं गौरव का क्षण है।

इस जानकारी को भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली को प्रेषित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जबरन/दबावपूर्वक मैनुअल स्केवेंजर्स का कार्य करवाने वाले व्यक्तियों हेतु दंड का भी प्रावधान है, जिसमें एक वर्ष का कारावास अथवा पचास हजार तक जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा मानवीय मूल्यों एवं संविधान द्वारा स्थापित उच्च आदर्शों के विपरीत है।

विधायक बोहरा ने पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण व वनांचल क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्रों के उन्नयन की मांग

श्रीकंचनपथ समाचार

कवर्धा। पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने विधानसभा में महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित प्रावधानों पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए पंडरिया विधानसभा के ग्रामीण व वनांचल एवं आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी सेवाओं के विस्तार और पोषण कार्यक्रमों को मजबूत करने की बात कही जिससे क्षेत्र की महिलाओं और बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आ सके।

इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र व प्रदेश से जुड़े प्रमुख विषयों को सदन के समक्ष रखा। उन्होंने ग्राम पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु स्वीकृत कार्यों और ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण व कंप्यूटर विहीन ग्राम पंचायतों के विषय में प्रश्न किया। ग्रामीण क्षेत्रों में जनता की सुविधा हेतु ऑनलाइन दस्तावेजों की प्राप्ति में ग्रामवासियों को हो रही असुविधा के लिए उन्होंने प्रमुखता से प्रश्न रखा साथ ही उन्होंने ग्रामीण विकास के लिए पंचायतों द्वारा स्वीकृत एवं लंबित कार्यों का विषय भी उठाया। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं एवं पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगार के विषय को भी प्रमुखता से रखा और प्रदेश व जिले में स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के विषय में भी प्रश्न किया।भावना बोहरा ने प्रश्न किया कि कबीरधाम जिले में वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में ग्राम पंचायतों के माध्यम से कितने विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं? स्वीकृत कार्यों पर अब तक कितनी राशि व्यय की जा चुकी है? इनमें से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने प्रगतिरत हैं? क्या उक्त स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता की नियमित निगरानी हेतु कोई विशेष तंत्र स्थापित किया गया है?

जिसके लिखित उत्तर में गृह मंत्री जी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में 15वें वित्त एवं मुलभुत योजनाओं के अंतर्गत कुल 6,254 कार्य स्वीकृत हुए हैं जिसके लिए 67 करोड़ 80 लाख 91 हजार रु स्वीकृत की गई और कुल 35 करोड़ 49 लाख 93 हजार रु व्यय किये गए हैं। इनमें से 3,573 कार्य पूर्ण हो चुके हैं, 1,373 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 1237 कार्य अप्रारम्भ हैं। 2024-25 एवं 2025-26 में कबीरधाम जिलें में ग्राम पंचायत के माध्यम से स्वीकृत कार्यो की गुणवत्ता की निगरानी उप अभियंता एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के द्वारा की जाती है। उन्होंने ग्राम पंचायतों में क्रय किये गये कम्प्यूटर के विषय में प्रश्न किया कि पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत संचालन के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि में कुल कितने कम्प्यूटर क्रय किए गए हैं तथा उक्त क्रय पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है?

जिसके लिखित उत्तर में मंत्री जी बने बताया कि पंडरिया विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पंचायत संचालन के प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 की अवधि में राज्य स्तर से निरंक, जिला/जनपद पंचायत स्तर से निरंक तथा पंचायत स्तर से कुल 07 कम्प्यूटर क्रय किए गए हैं। इनमें से जनपद पंचायत पंडरिया में 3, कवर्धा में 2 तथा सहसपुर लोहरा में 2 कम्प्यूटर कुल लागत 4 लाख 61 हजार 490 रु. में क्रय किया गया है।

130 दिव्यांगजनों का पंजीयन, 20 हितग्राहियों को सहायक उपकरण वितरित

श्रीकंचनपथ समाचार

जशपुरनगर। शिविर में दिव्यांगजनों के दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड बनाए गए तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित आवेदन भी प्राप्त किए गए।

शिविर के दौरान दिव्यांगजनों से पेंशन योजनाओं, सहायक उपकरण, बस पास, ऋण सुविधा तथा दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना सहित अन्य योजनाओं के लिए आवेदन लिए गए। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि पिंकी गुप्ता जनपद पंचायत सदस्य, पूर्व जनपद पंचायत सदस्य दिनेश गुप्ता, उपसंचालक समाज कल्याण धर्मेन्द्र साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दुलदुला पुष्कर पटले तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जी.एस. जात्रा भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा 20 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। इनमें हस्तचलित ट्रायसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र, वैशाखी एवं वॉकिंग स्टिक शामिल हैं। साथ ही पात्र हितग्राहियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड भी प्रदान किए गए। शिविर में कुल 130 दिव्यांगजनों का पंजीयन किया गया। इनमें से 52 दिव्यांगजनों के प्रमाण पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड बनाए गए, जबकि 16 प्रकरणों को जिला अस्पताल के लिए रिफर किया गया। इसके अलावा 5 दिव्यांगजनों ने ऋण योजना हेतु आवेदन किया, 1 आवेदन दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना के लिए प्राप्त हुआ, 10 आवेदन पेंशन हेतु प्राप्त हुए तथा 6 दिव्यांगजनों ने पेंशन से संबंधित जानकारी प्राप्त की।

शिविर में 20 दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण प्रदान किए गए तथा 1 दिव्यांगजन को कृत्रिम अंग निर्माण के लिए चिन्हांकित किया गया।

खास खबर

पुलिस ने नाकाम की साजिश 51.41 लाख का गांजा बरामद

जगदलपुर। जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बोधघाट पुलिस ने एक अंतरराज्यीय गिरोह के नेटवर्क को ध्वस्त करते हुए दो शातिर तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। इस पूरी कार्रवाई में पुलिस ने लगभग 102.82 किलोग्राम अवैध गांजा जब्त किया है, जिसकी बाजार में अनुमानित कीमत 51 लाख 41 हजार रुपये बताई जा रही है। यह खेप ओडिशा से तस्करी कर बस्तर के रास्ते खपाने की तैयारी थी, लेकिन मुखबिर ने तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। आड़ावाल रेलवे फाटक के पास एक संदिग्ध व्यक्ति भारी मात्रा में नशीले पदार्थ के साथ ग्राहक की तलाश में खड़ा है। घेराबंदी कर जब संदेही को पकड़ा गया, तो उसने भागने की कोशिश की, जिसे जवानों ने दबोच लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से शुरुआती तौर पर गांजे की खेप बरामद हुई। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने अपने मुख्य सप्लायर का राज उगल दिया, जो पड़ोसी राज्य ओडिशा के रायगढ़ा जिले से इस पूरे काले कारोबार का संचालन कर रहा था। इसके बाद पुलिस की एक टीम ने ओडिशा के दाबलीगुड़ा में दबिश दी। वहां से मुख्य सप्लायर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया।

मेटाडोर और डीजे सिस्टम जब्त, संचालक गिरफ्तार

जांजगीर। जिले में देर रात तेज आवाज में डीजे बजाने वाले संचालकों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कोतवाली पुलिस ने बुधवार की रात चांपा रोड पर कार्रवाई करते हुए डीजे संचालक को गिरफ्तार कर मेटाडोर और उसमें लगा डीजे सिस्टम जब्त किया है। कोतवाली पुलिस के अनुसार एसपी विजय कुमार पांडेय ने सभी थाना प्रभारियों की बैठक लेकर डीजे संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिले में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार की रात पुलिस को सूचना मिली कि चांपा रोड में मेटाडोर में डीजे लगाकर तेज आवाज में संगीत बजाया जा रहा है। थाना प्रभारी जयप्रकाश गुप्ता के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने डीजे संचालक कोरबा बालको निवासी ज्योतिष कश्यप (30) को फौरन हिरासत में ले लिया। इसके बाद मेटाडोर और उसमें लगे डीजे सिस्टम को जब्त किया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

दो बाइक की जबरदस्त टक्कर एक की मौत, 3 घायल

कोरबा। कोरबा के उरगा थाना क्षेत्र में मड़वारानी के पास चांपा मुख्य मार्ग पर दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में तीन अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को जिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना गुरुवार देर रात हुई। जानकारी के अनुसार, एक बाइक पर तीन लोग चांपा से कोरबा की ओर आ रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर सवार एक युवक कोरबा से चांपा की तरफ जा रहा था। बताया जा रहा है कि एक बाइक चालक गलत दिशा में था, जिसके कारण यह टक्कर हुई। मृतक की पहचान जांजगीर-चांपा जिले के कमरीद सरगांव निवासी 18 वर्षीय निखलेश कंवर के रूप में हुई है। हादसे में उसके सिर पर गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हो गई। परिजनों को सूचना दे दी गई है, जो देर रात कोरबा पहुंचे और घटना की जानकारी ली। बाइक पर सवार तीन अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं और उनका इलाज जारी है। जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने मेमो के आधार पर मृतक के परिजनों के बयान दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।

मजदूरी कर रहे 7 नाबालिगों का रेस्क्यू इंद्राक्षी प्लांट समेत 4 पर किया केस दर्ज

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर के औद्योगिक क्षेत्रों में नाबालिगों को बंधक बनाकर काम कराने वाले कारोबारियों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। उरला, सिलतरा और खमतराई इलाके के फैक्ट्री-कारखानों में दबिश देकर एनजीओ, पुलिस की संयुक्त टीम ने 7 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया।

ये मासूम अपनी उम्र के विपरीत भारी मशीनों और खतरनाक रसायनों के बीच मजदूरी करने को मजबूर थे। जिन संस्थानों में छापेमारी की गई, उनमें सोनी प्लाईवुड इंडस्ट्री, शैमरॉक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, इद्राक्षी पाली प्लास्टर एलएलपी प्लांट और सन लॉजिस्टिक एंड डिस्ट्रीब्यूटर शामिल हैं। पुलिस ने कंपनी संचालकों के साथ शैमरॉक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड में नाबालिग से काम कराने वाले ठेकेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई

एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन छत्तीसगढ़ (एवीए) के रायपुर समन्वयक विपिन ठाकुर ने बताया कि उरला, सिलतरा और खमतराई इलाके में संचालित कंपनियों के प्रबंधन-ठेकेदारों के खिलाफ नाबालिग बच्चों से काम कराने की लगातार शिकायतें मिल रही थी।

लगातार शिकायत मिलने पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद चार फर्मों के कारखानों में छापेमारी की गई। कार्रवाई के दौरान उरला इलाके से तीन और खमतराई इलाके से चार नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया। इन बच्चों से उद्योगों व बेकरी में काम कराया जा रहा था। मामले की पूरी रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी गई है।

वेल्डिंग, लोडिंग व पैकिंग जैसे कठिन काम

छापेमारी करने वाली टीम के अनुसार औद्योगिक इलाकों के चार अलग-अलग ठिकानों पर जांच की गई। इस दौरान फैक्ट्रियों के भीतर छोटे बच्चों से वेल्डिंग, लोडिंग और पैकिंग जैसे कठिन काम कराए जा रहे थे।

इन सभी संस्थानों के मालिकों और प्रबंधकों के खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। रेस्क्यू किए गए सातों नाबालिगों का मेडिकल परीक्षण कराया गया। इसके बाद उन्हें बाल कल्याण समिति (सीडब्लू) के समक्ष पेश किया गया। फिलहाल बच्चों को सुरक्षित बाल गृह भेज दिया गया है, जहां उनकी काउंसलिंग की जा रही है।

अधिकारियों का कहना है कि बच्चों के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है। साथ ही यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि रायपुर को बाल श्रम मुक्त बनाया जा सके।

5 महीने पहले भी मशरूम फैक्ट्री से रेस्क्यू किए गए थे नाबालिग

रायपुर में बाल मजदूरी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले खरोरा स्थित मोजो मशरूम फैक्ट्री में भी बाल श्रमिकों के शोषण का मामला सामने आया था। उस मामले को करीब पांच महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 17 नवंबर को वहां से 109 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया गया था। एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) और बजरंग दल की शिकायत के बाद दिल्ली से आई मानवाधिकार आयोग की टीम, महिला बाल विकास विभाग तथा पुलिस ने छापेमारी की थी।

इस कार्रवाई में 68 बच्चियां और 41 बच्चों को बाल मजदूरी से मुक्त कराया गया था।

कारोबारी के 10 लाख रुपए लेकर मुंशी फरार, पुलिस ने शुरु की जांच

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी के गंज थानाक्षेत्र में कारोबारी का 10 लाख रुपए लेकर मुंशी फरार हो गया। कारोबारी की शिकायत पर गंज पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच में लिया है।

कारोबारी का नाम पुलिस द्वारा विजय गोयल और आरोपी मुंशी का नाम अनिल साल्वे बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ जांच गंज पुलिस कर रही है।

देवेंद्र नगर निवासी कारोबारी विजय गोयल ने पुलिस को बताया, कि उसकी 'आयरन एंड स्टील ट्रेडिंग' की कंपनी है। अरिहंत कार्यालय स्टेशन रोड में उसका ऑफिस है। कंपनी के पैसों को पार्टियों से लाने और उसे बैंक में जमा करने की जिम्मेदार अनिल साल्वे को दी थी।

अनिल साल्वे ने पार्टियों से 10 लाख रुपए कंपनी का लिया, लेकिन उसे बैंक में जमा नहीं करके फरार हो गया। कारोबारी ने अनिल को फोन किया, लेकिन उसका फोन भी बंद बता रहा है। कारोबारी की शिकायत पर गंज पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरु कर दी है।

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर तलाश जारी

गंज निरीक्षक सुनील दास ने बताया, कि कारोबारी की शिकायत पर मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी अनिल साल्वे के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले में जांच की जा रही है।

रायपुर आ रहे यात्री बाल-बाल बचे, बस में लगी भीषण आग

जशपुर। रांची से रायपुर के लिए जशपुर होते हुए चलने वाली शिवनाथ बस में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। यह घटना उस समय हुई जब बस रांची के खड़गढ़ा बस स्टेण्ड से रवाना होने के बाद नकुम क्षेत्र में रिंग रोड पर पहुंची थी। बस में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी बस धू-धू कर जलने लगी। बस में आग लगने की भनक लगते ही चालक ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत यात्रियों को इसकी सूचना दी और बस को सड़क किनारे रोक दिया। इसभी यात्रियों को जल्द से जल्द बस से नीचे उतार दिया गया। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में बस पूरी तरह आग की चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।

ज्वैलरी लेकर पैसे लाने की बात कहकर फरार हुए पति-पत्नी

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायपुर। राजधानी रायपुर के टिकरापारा इलाके में सराफा कारोबारी से ठगी का शिकार बनाया गया है। पति-पत्नी दुकान पर पहुंचे और करीब 5 लाख रुपए की ज्वैलरी लेकर पैसे लाने की बात कहकर फरार हो गए। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला टिकरापारा थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक कारोबारी का नाम दुर्गा प्रसाद सोनी, जबकि आरोपियों के नाम कमलेश्वरी साहू और मेशराम साहू

बताया जा रहा है। फिलहाल, पुलिस दुकान और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, ताकि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।

टिकरापारा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दुर्गा प्रसाद सोनी देवपुरी में 'मां दुर्गा ज्वेलर्स' नाम से दुकान संचालित करते हैं। गुरुवार 12 मार्च की शाम उन्होंने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। कारोबारी ने बताया कि कमलेश्वरी साहू और मेशराम साहू उनकी दुकान पर ज्वैलरी खरीदने पहुंचे थे। दोनों ने सोने का रानी हार, बाली, अंगूठी, चांदी की पायल और बिछिया सहित करीब 4 लाख 93 हजार रुपए की ज्वैलरी पसंद की। उन्होंने पसंद की गई ज्वैलरी पहन ली और कहा कि वे परिचितों से पैसे लेकर आते हैं। यह कहकर दोनों दुकान से निकल गए, लेकिन वापस नहीं लौटे।

थाना प्रभारी विनय सिंह ने बताया कि कुशालपुर, पुरानी बस्ती निवासी दुर्गा प्रसाद सोनी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, ताकि आरोपियों के भागने के रास्ते का पता चल सके। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान हो चुकी है और जल्द ही गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी।

रायगढ़ में प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा ओवरलोड ट्रेलर पलटा

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। शहर के चक्रधर नगर चौक के पास बुधवार की रात प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसा ओवरलोड ट्रेलर पलट गया। ट्रेलर में लोड आयरन पाइलेट सड़क पर बिखर जाने से कुछ समय के लिए मार्ग बाधित हो गया। सूचना मिलते ही चक्रधर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क साफ कराकर यातायात बहाल कराया। पुलिस ने चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की है।

ट्रेलर क्रमांक सीजी 13 एके 4986 का चालक पुष्पराज साहू (25) निवासी ग्राम सिलवार, थाना जोगी पहरी, जिला सीधी, बुधवार रात वाहन को खतरनाक तरीके से चलाते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में ले आया। ट्रेलर अनियंत्रित

होकर पलट गया और उसमें लोड आयरन पाइलेट सड़क पर फैल गई, जिससे आवागमन कुछ देर प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सड़क पर फैली आयरन पाइलेट हटाने के लिए जेसीबी बुलाई गई। पुलिस की मौजूदगी में देर रात तक साफ-सफाई कराकर मार्ग को पूरी तरह साफ कराया गया। जांच में पाया गया कि ट्रेलर में क्षमता से करीब 25 टन अधिक आयरन पाइलेट लोड था। इसके अलावा वाहन का बीमा भी नहीं मिला। इस पर चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई है।

नो एंट्री में घुसे वाहनों पर भी हुई कार्रवाई: देर रात चक्रधर नगर पुलिस ने प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वाले अन्य भारी वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई की। इनमें हाईवा क्र. सीजी 13 बीसी 6434 , ट्रक क्र. ओडी 09 के 4445 और ट्रक ओडी 09 क्यू 2601 शामिल हैं। चालकों को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया।

नारायणपुर में सवारी से भरी पिकअप पलटी, तीन की मौत कई घायल

नारायणपुर। जिले में नारायणपुर-ओरछा मुख्य मार्ग पर ग्राम झारा घाटी के पास हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए।

बताया जाता है कि एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से पलट गई जिसमें 30 से ज्यादा लोग सवार थे। दुर्घटना में 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 25 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलते ही 108 संजीवनी एंबुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि पिकअप वाहन का इस्तेमाल सवारी ढोने के लिए किया जा रहा था, जबकि इस तरह के वाहनों में यात्रियों को ले जाने पर पाबंदी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

रायगढ़ में 5 उद्योगों पर 13.96 लाख का जुर्माना

सुरक्षा मानकों में बरती गई लापरवाही, निरीक्षण में मिला नियमों का उल्लंघन

श्रीकंचनपथ न्यूज

रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के उद्योगों में लगातार हो रही घटनाओं और मजदूरों की मौत के मामलों को गंभीरता से लिया गया है। जांच में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आने पर औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की।

इसके बाद श्रम न्यायालय में केस दर्ज किए गए, जहां अदालत ने 5 उद्योगों पर कुल 13 लाख 96 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग के उपसंचालक राहुल पटेल ने बताया कि जिले की कई फैक्ट्रियों में दुर्घटनाएं हुई थीं। इन घटनाओं के बाद विभागीय टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। निरीक्षण के दौरान कई जगहों पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन और लापरवाही

सामने आई।

जांच में लापरवाही मिलने पर संबंधित उद्योगों के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली 1962, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 और छत्तीसगढ़ भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियम 2008 के प्रावधानों के तहत आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय में दर्ज किए गए। मामलों की सुनवाई के बाद श्रम न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए पांच उद्योगों पर कुल 13 लाख 96 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया।

सुरक्षा मानकों की लगातार हो रही अनदेखी

उपसंचालक राहुल पटेल ने बताया कि रायगढ़ जिले के कारखानों की लगातार जांच की जा रही है, ताकि उद्योगों में सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। इसके बावजूद कई जगहों पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आ रही है, जिसके चलते ऐसे मामलों में श्रम न्यायालय में केस दर्ज किए गए।

इन उद्योगों पर लगाया गया जुर्माना

- मेसर्स विष्णु ब्रिक्स, ग्राम उपरकछार जिला जशपुर- 3 लाख 50 हजार रुपए।
- मेसर्स इंड सिनर्जी, ग्राम कोटमार - 8 हजार रुपए।
- मेसर्स एजी कंस्ट्रक्शन, महापल्ली - 8 हजार रुपए।

अफीम की अवैध खेती के मामला में चौथा आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार

श्रीकंचनपथ न्यूज

भिलाई। दुर्ग जिले के समोदा-झेनझरी गांव के बीच अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती के मामले में पुलिस को एक और सफलता मिल है। दुर्ग पुलिस ने इस मामले में चौथे आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। आरोपी छोटू राम को थाना चोमे उदयपुर से गिरफ्तार किया गया। छोटू राम द्वारा अफीम की खेती के लिए बीज उपलब्ध कराए जाने की जानकारी सामने आई है।

बता दें थाना पुलगांव क्षेत्रांतर्गत चौकी ग्राम समोदा, झेनझरी एवं सिरसा के मध्य स्थित भूमि में अवैध रूप से अफीम की खेती किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची एवं शून्य में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। निरीक्षण के दौरान खेत में मक्का/भुट्टे की फसल के बीच-बीच में अफीम के पौधे लगाए पाए गए। संयुक्त टीम द्वारा खेत का निरीक्षण कर लगभग 05 एकड़ 62 डिसमिल क्षेत्र में लगे अफीम के पौधों को जप्त किया गया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 08 करोड़ आंकी गई। मामले में NDPS Act के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की गई।

विवेचना के दौरान पूर्व में विकास बिश्नोई निवासी मतोड़ा जिला जोधपुर (राजस्थान), विनायक ताम्रकार निवासी तेमरापारा दुर्ग एवं मनीष उर्फ गोलू ठाकुर निवासी समोदा को गिरफ्तार किया गया था।

दुर्ग, थाना पुलगांव एवं चौकी जेवरा-सिरसा की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी छोटू राम को राजस्थान से गिरफ्तार किया गया। छोटू राम के पास से मोबाइल, 2220 रुपए नगद जब्त किया गया है। प्रकरण में आगे की विवेचना एवं वैधानिक कार्रवाई जारी है।

।। न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग-4 जिला दुर्ग (छ.ग.) ।।

रा.प्र.क्र/202603104100009/अ-19(3)/
वर्ष 2025-2026
ग्राम:- दमोदा प.ह.नं. 01

उद्घोषणा

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय कलेक्टर (आबंटन) दुर्ग के पृष्ठांकन क्रमांक 604 / आबंटन / 2026 दुर्ग, दिनांक 28-1-2026 एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग के पृष्ठां.क्रमांक 276/ अविअ/2025 दुर्ग, दिनांक 2-2-2026 के द्वारा कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं दुर्ग के ज्ञा. क्रमांक / उपंदु/साख / 2026 / 131 दुर्ग, दिनांक 19-1-2026 के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के सहकार से समृधि संकल्पना के परिपालन में प्रत्येक ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय पैक्स/दुग्ध /मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना संबंधी भारत सरकार सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किये गये पहल अंतर्गत सहकारिता विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का पुनर्गठन कर 515 नवीन पैक्स का गठन किया गया है। नवगठित पैक्स को दिनांक 15-4-2026 से कार्यशील किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अनुक्रम में विभाग द्वारा तैयार समयबद्ध कार्ययोजना अंतर्गत नवगठित पैक्स के लिये कार्यालय सह गोदाम निर्माण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. दुर्ग द्वारा नवीन समिति जिला दुर्ग के अंतर्गत तहसील दुर्ग के ग्राम दमोदा प0ह0नं0 01 रा0नि0म0 नगपुरा में स्थित भूमि खसरा नंबर 375 रकबा 1.040 हेक्टेयर भूमि को सहकारिता विभाग के नाम से आबंटन करने हेतु जांच प्रतिवेदन हेतु प्राप्त हुआ है। जो कि प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।

यदि जिस किसी भी व्यक्ति को उक्त भूमि को सहकारिता विभाग के नाम पर आबंटन करने से कोई आपत्ति दावा या उजर हो तो स्वयं इस न्यायालय में पेशी दिनांक 24 मार्च, 2026 को लिखित में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

जारी दिनांक 9-3-2026
पेशी दिनांक 24-3-2026

नायब तहसीलदार
दुर्ग (छ.ग.)

शराब के नशे में स्कूल पहुंचे दो शिक्षक निलंबित

बिलासपुर। स्कूल में शराब के नशे में पहुंचने के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए मस्तूरी विकासखंड के दो सहायक शिक्षकों को निलंबित कर दिया है। दोनों मामलों में स्थानीय शिकायत, जांच और स्पष्टीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद यह कार्रवाई की गई। पहला मामला ग्राम पंचायत जुनवानी स्थित शासकीय प्राथमिक शाला का है। 6 मार्च को ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि स्कूल निरीक्षण के लिए पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान वहां पदस्थ सहायक शिक्षक संदीप रात्रे शराब के नशे में पाए गए। दूसरा मामला मस्तूरी ब्लॉक के पीएमश्री शासकीय प्राथमिक शाला कुकुर्दीकला का है। यहां पदस्थ सहायक शिक्षक उत्तम कुमार कंवर के खिलाफ भी शराब पीकर स्कूल आने की शिकायत मिली थी।

छत्तीसगढ़ शासन

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 वर्षों का उत्सव वर्षों का संकल्प

डबल इंजन की सरकार में विकास सुपरफास्ट

- **रावघाट- जगदलपुर रेल परियोजना** के साथ रेल नेटवर्क मैप से जुड़ रहा बस्तर
- **पीएम जनमन योजना** के साथ जनजाति समुदाय का हो रहा विकास
- दक्षिण छत्तीसगढ़ में **बोधघाट परियोजना** बनेगी हरियाली और समृद्धि का वरदान
- **महतारी वंदन** से महिलाओं को संबल
- किसानों को बकाया बोनस, **पीएम किसान सम्मान निधि** का भी लाभ
- **26 लाख से अधिक** परिवारों को अपना पक्का आवास
- जगदलपुर - विशाखापत्तनम और रायपुर-विशाखापट्टनम **नई सड़क परियोजनाओं** से विकास की नई राहें
- स्पष्ट नीति और मजबूत निर्णयों के साथ **सुशासन का राज**

RO-45320/7

हमसे जुड़ने के लिए QR स्कैन करें

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

सुशासन से समृद्धि की ओर

ChhattisgarhCMO | DPRChhattisgarh | www.dprcg.gov.in

श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक, प्रकाशक राजेश अग्रवाल द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि. छत्तीसगढ़ भवन, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित कर, 204 आकाशगंगा सुपेला, भिलाई जिला दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित। संपादक राजेश अग्रवाल shreekanchanpath2010@gmail.com, Mo - 9303289950